



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]  
No. 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 25, 1987/श्रावण 3, 1909  
NEW DELHI, SATURDAY, JULY 25, 1987/SRAVANA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than  
the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1987

सूचना

का आ 1876—नोटरीय नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री राजेन्द्र मोहन, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी की उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे होशियारपुर (पंजाब) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[स 5(42)/87 न्या.]

आर. एन. पोद्दार,

सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 13th July, 1987

NOTICE

S.O. 1876.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries, 1956, that application has been made to the said Authority, under

615 GI/87—1

rule 4 of the said Rules, by Shri Rajinder Mohan Advocate for appointment as a Notary to practise in Hoshiarpur.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(42)/87-Judl.]

R. N. PODDAR, Competent Authority

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

सा० आ० 1877 - केन्द्रीय सरकार राजभाषा (सब के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4), के अनुसरण में, सांख्यिकी विभाग के निम्नलिखित कार्यालय जिसमें कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यभाषक ज्ञान प्राप्त कर लिया है को अधिसूचित करती है —

समक विधायन केन्द्र, समक विधायन प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली।

[सं० ई०-11011/6/83-हिन्दी]

जोगेन्द्र सिंह, अवर सचिव

(2465)

## MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 6th July, 1987

S.O. 1877.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Office of the Department of Statistics, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

Data Processing Centre, Data Processing Division,  
National Sample Survey Organisation,

New Delhi.

[No. E-11011/6/83-Hindi]

JOGINDER SINGH, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

आयकर

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1987

का.प्रा. 1878.—इस कार्यालय की दिनांक 25-2-86 की अधिसूचना सं. 6603(फा.स. 203/175/85 प्रा.क. नि-II) के मिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैनीम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि सी.सी. श्रोफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलनपत्र की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर प्राधिकृत को भेजेगा।
- (iv) यह कि उक्त संस्था केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अधिवृद्धि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्राप्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"सी.सी. श्रोफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, 903, आंसल भवन,

कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001,

यह अधिसूचना 1-1-1987 से 31-12-89 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7182(फा.स. 203/178/86 प्रा.क. नि-II)]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th March, 1987

S.O. 1878.—In continuation of this Office Notification No. 6603 (F. No. 203/175/85-ITA-II) dated 25-2-86 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five|One|Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the C.C. Shroff Research Institute, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

## INSTITUTION

C. C. Shroff Research Institute, 903, Ansal Bhavan,  
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001.

This Notification is effective for a period from 1-1-87 to 31-12-1989.

[No. 7182 (F No 203/178/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1987

का.प्रा. 1879.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैनीम/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि संज्ञाता मेडिकल रिसर्च, सोमायटी, मिराज अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलनपत्र की एक एक प्रति, प्रति वर्ष

30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“संघाता मेडिकल रिसर्च, सोसाइटी, मिराज 616410”

यह अधिसूचना 20-1-1986 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 7194(फा. स. 203/28/86आ. क. नि II)]

New Delhi, the 19th March, 1987

S.O. 1879.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Scientific & Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) That the Sandhata Medical Research Society, Miraj will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

Sandhata Medical Research Society, Miraj-416410

This Notification is effective for a period from 20-1-1986 to 31-3-1987.

[No. 7194 (F. No. 203/28/86-ITA-II)]

का. आ. 1880.—सबसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पतीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए “संगम” प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (i) यह कि हस्तीमल संचेती रिसर्च फाउण्डेशन, पुणे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

- (ii) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

- (iii) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्ति दनदारियां दर्शाते हुए तुलन पत्र की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

- (iv) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

“हस्तीमल संचेती रिसर्च फाउण्डेशन, 16, शिवाजी नगर पुणे-411005, ”

यह अधिसूचना 17-2-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 7195(फा.स. 203/189/84 आ. क. नि II)]

S.O. 1880.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) That the Mastimal Sanchati Research Foundation, Pune, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

Hastimal Sanchati Research Foundation, 16, Shivaji Nagar, Pune-411005.

This Notification is effective for a period from 17-2-1986 to 31-3-1988.

[No. 7195 (F. No. 203/189/84-ITA-II)]

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1987

का. भा. 1881:—इस कार्यालय की दिनांक 18-8-1982 की अधिसूचना सं. 4872 (फा. सं. 203/151/77-भा. क. नि.-ii) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पेंसीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (1) यह कि व मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिषिक्त किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वशाति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां वशाति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"द मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, 2 हैली रोड, नई दिल्ली-110001,

यह अधिसूचना 6-7-1984 से 31-12-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7203 (फा. सं. 203/29/87-भा.क. नि.-II)]

New Delhi, the 26th March, 1987

S.O. 1881.—In continuation of this Office Notification No. 4872 (F. No. 203/151/77-ITA-II) dated 18-8-1982, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/Two) of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category Association, subject to the following conditions:—

- (i) That the Mother's Institute of Research, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing

its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

"The Mother's Institute of Research 2, Hailey Road, New Delhi-110001."

This Notification is effective for a period from 6-7-1984 to 31-12-1987.

[No. 7203 (F. No. 203/29/87-ITA-II)]

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1987

का. भा. 1882:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पेंसीस/एक/दो) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (1) यह कि रोडरी माई इंस्टीट्यूट डी. एन. गोहिल सेंटर फॉर प्रायथालमोलोजीकल रिसर्च, गुजरात अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिषिक्त किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय वशाति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां वशाति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"रोडरी माई इंस्टीट्यूट डी. एन. गोहिल सेंटर फॉर प्रायथालमोलोजीकल रिसर्च, इंधिया तलाब, नवसारी, गुजरात-396445"

यह अधिसूचना 17-2-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7208 (फा. सं. 203/185/86-भा. क. नि.-II)]

New Delhi, the 30th March, 1987

S.O. 1882.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the

Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category Association, subject to the following conditions :—

- (i) That the Rotary Eye Institute D. N. Gohil Centre for Ophthalmological Research, Gujarat will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi, and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

"Rotary Eye Institute D. N. Gohil Centre For Ophthalmological Research, Dudhia Talao, Navsari, Gujarat-396445."

This Notification is effective for a period from 17-2-1987 to 31-3-1988.

[No. 7208 (F. No. 203/185/86-ITA-II)]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1987

का. भा. 1883 :—इस कार्यालय की दिनांक 3-9-1983 की अधिसूचना सं. 5378 (फा. सं. 203/67/83-मा. क. नि.-II) के तिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को धायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित धायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैनीस/एक/सो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रयोग के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (1) यह कि द इंस्टीच्यूट ऑफ इण्डियन फाउण्ड्रीमैन, कलकत्ता अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय वृत्ति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियों, वैनशानियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन वस्तावों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित धायकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को धामोक्स की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा।

आवेदन प्रस्तुत करने में किसी अवकाश को बेरी होने पर प्रावना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

#### संस्था

"द इंस्टीच्यूट ऑफ इण्डियन फाउण्ड्रीमैन, "मिडिलटॉन कोर्ट"  
मिडिलटॉन स्ट्रीट, कलकत्ता-700071."

यह अधिसूचना 9-2-1986 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[न. 7221 (फा. सं. 203/43/87-मा. क. नि.-II)]

वाई. के. बत्रा, अधर सचिव

New Delhi, the 6th April, 1987

S.O. 1883.—In continuation of this Office Notification No. 5378 (F. No. 203/67/83-ITA-II) dated 3-9-1983, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five, One/Two) of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution", subject to the following conditions :—

- (i) That The Institute of Indian Foundrymen, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (v) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

"The Institute of Indian Foundrymen 'Middleton Court',  
4/2, Middleton Street, Calcutta-700071."

This Notification is effective for a period from 9-2-1986 to 31-3-1988.

[No. 7221 (F. No. 203/43/87-ITA-II)]

Y. K. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1987

#### धायकर

का. भा. 1884 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को धायकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित धायकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैनीस/एक/

दो) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रथम के अधीन, निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है:—

- (1) यह कि श्री जयदेव इंस्टीच्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बंगलूर अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"श्री जयदेव इंस्टीच्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, बिक्टोरिया  
हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, बंगलूर-560002",

यह अधिसूचना 26-2-1987 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7242 (फा. सं. 203/57/86-आ. क. नि. -II)]

New Delhi, the 10th April, 1987

S.O. 1884.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961, read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution", subject to the following conditions:—

- (i) That the Sri Jaydeva Institute of Cardiology, Bangalore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

## INSTITUTION

"Sri Jayadeva Institute of Cardiology, Victoria Hospital Complex, Bangalore-560002."

This Notification is effective for a period from 28-2-1987 to 31-3-1989.

[No. 7242 (F. No. 203/57/86-ITA-II)]

फा. सं. 1885 :—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग और बीमा विभाग) की दिनांक 13-7-1973 की अधिसूचना सं. 419 (फा. सं. 203/23/73-आ. क. नि.-II) द्वारा स्किन इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i) (ii) के अधीन दिया गया स्थायी अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर समयबद्ध अनुमोदन में परिवर्तित किया जाता है जो कि 31-12-1987 तक वैध होगा:—

- (1) यह कि स्किन इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और सम्बन्धित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संस्थान, अवधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना-पत्र रद्द किया जा सकता है।

[सं. 7239 (फा. सं. 203/58/87-आ. क. नि. -II)]

S.O. 1885.—It is hereby notified for general information that the perpetual approval granted under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to Skin Institute, New Delhi vide Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 419 (F. No. 203/23/73-ITA-II) dated 13-7-73 is hereby converted into time bound approval valid upto 31-12-1987, subject to the following conditions:—

- (i) That the Skin Institute, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets, liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

[No. 7239 (F. No. 203/58/87-ITA-II)]

का. प्रा. 1886.—इस कार्यालय की दिनांक 31-3-1984 की अधिसूचना सं. 5734 (फा. सं. 203/15/84-प्रा. क. नि.-II) के मिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (ii) (पैरोस/एफ/शे) के प्रयोजनों के लिए "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

- (1) यह कि आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन सोसायटी फार प्रमोशन ऑफ मेडिकल रिसर्च, बम्बई अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हूए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दशति हूए तुलनपत्र की एक प्रति, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली और संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"आल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन सोसायटी फार प्रमोशन ऑफ मेडिकल रिसर्च हाज़ि अली पार्क, महानगरी बम्बई-400034."

यह अधिसूचना 20-12-1986 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 7240 (फा. सं. 203/266/86-प्रा. का नि. II)]

S.O. 1886.—In continuation of this Office Notification No. 5734 (F. No. 203/15/84-ITA.II) dated 31-3-1984, it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) That the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Society For Promotion of Medical Research, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation Society for Promotion of Medical Research, Hazi Ali Park, Mahalaxmi, Bombay-400034.

This Notification is effective for a period from 20-12-1986 to 31-3-1989.

[No. 7240 (F. No. 203/266/86-ITA-II)]

का.प्रा. 1887.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय की दिनांक 23/9/1967 की अधिसूचना सं. 107 (फा. सं. 10/46/66-प्रा. क. नि.-1) द्वारा निम्नलिखित संस्था को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत दिया गया स्थायी अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों पर समयबद्ध अनुमोदन में परिवर्तित किया जाता है जो कि 31-3-1987 तक बंध होगा :—

- (1) यह कि ट्यूबर क्लोसिज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।
- (2) यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।
- (3) यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हूए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दशति हूए तुलनपत्र की एक एक प्रति प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इस दस्तावेजों की एक एक प्रति सम्बन्धित आयकर आयुक्त तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली को भेजेगा।
- (4) यह कि उक्त संगम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के उपबन्धों के अन्तर्गत निवेश के सम्बन्ध में नियमों का संशोधन करेगा।
- (5) यह कि उक्त संगम अवधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द किया जा सकता है।

संस्था

"ट्यूबर क्लोसिज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, रेड ग्राम रोड, नई दिल्ली-110001"

[सं. 7215 (फा. सं. 203/211/86-प्रा. का नि.-II)]

S.O. 1887.—It is hereby notified for general information that the perpetual approval granted under clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 to the following Institution vide Ministry of Finance Notification No. 107 (F. No. 10/46/66-IT(AI)) dated 23-9-1967 is hereby converted into time bound approval valid upto 31-3-87 subject to the following conditions :—

- (i) That the Tuberculosis Association of India, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

- (ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax and the Central Board of Direct Taxes, New Delhi.
- (iv) That the said Association will amend the rules regarding investment to be in conformity with the provisions of Section 11(5) of the Income-tax Act, 1961.
- (v) That the said Association will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

"The Tuberculosis Association of India, Red Cross Road, New Delhi-110001."

[No. 7245 (F. No. 203/211/86-ITA.II)]

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1987

का. आ. 1888—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली, ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) (पैरिस/एक/तीन) के प्रयोजनों के लिए "संस्था" प्रथम के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

(1) यह कि यह वर्ल्ड डेवेलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए स्वयं द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणों, विहित प्राधिकारी को अत्यधिक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 31 मई तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जो इन प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाने हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाने हुए तुलन पत्र की एक एक प्रति, प्रति वर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली तथा संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

(4) यह कि उक्त संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) नई दिल्ली को अनुमोदन की समाप्ति से तीन माह पूर्व और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। आवेदन प्रस्तुत करने से किसी प्रकार की देरी होने पर प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

संस्था

"वर्ल्ड डेवेलपमेंट सेंटर आफिस कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट राउण्ड सर्किल, बी-97, कालकाजी, नई दिल्ली-110019"

यह अधिसूचना 17-2-1987 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 7252 (का. स. 203/177/86/आ.क. नि.-II)]

श्रीमती एस. अनु. उप सचिव

New Delhi, the 21st April, 1987

S.O. 1888.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Third World Development Centre, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 31st May each year.
- (iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and Balance Sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the Central Board of Direct Taxes, New Delhi and the concerned Commissioner of Income-tax.
- (iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance (Department of Revenue), New Delhi, 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

#### INSTITUTION

"Third World Development Centre, Office Complex, First Round Circle, B-97, Kalkaji, New Delhi-110019."

This Notification is effective for a period from 17-2-1987 to 31-3-1988.

[No. 7252 (F. No. 203/177/86-ITA.II)]

MRS. S. BASU, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1987

(शुद्धिपत्र)

आयकर

का. आ. 1889—दिनांक 15 नवम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड (ii) के पृष्ठ 4523 पर प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 29 अक्टूबर, 1986 की अधिसूचना सं. का. आ. 3829 की 5वीं पंक्ति में "नई दिल्ली" के स्थान पर बम्बई पढ़ा जाए।

[सं. 7343 (का. सं. 275/52/86 आ. क. (ब))]

बा. नगराजन, निदेशक,

New Delhi, the 15th June, 1987

#### CORRIGENDUM

#### INCOME-TAX

S.O. 1889.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. S.O. 3829, dated the 29th October, 1986, published at pages 4523 of the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 15th November, 1986, in line 5, for "New Delhi", read "Bombay".

[No. 7343 (F. No. 275/52/86-IT (B))]

B. NAGARAJAN, Director



नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1890.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.ए. द्वारा उक्त शुल्क को माफ करती है, जो पंजाब वित्त निगम, चण्डीगढ़ द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र तीन लाख रुपये मूल्य के 12.5 प्रतिशत पंजाब वित्त निगम बन्ध-पत्र, 1996 (31वीं श्रृंखला) के बचत-पत्रों के स्वरूप के बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[संख्या 29/87/स्टाम्प. का. सं 33/70/86 वि. कर]

New Delhi, the 6th July, 1987

ORDER

STAMPS

S.O. 1890.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes, 12.5 per cent Punjab Financial Corporation Bonds 1996 (31st Series) of the value of rupees three hundred and thirty lakhs only to be issued by Punjab Financial Corporation, Chandigarh are chargeable under the said Act.

[No. 29/87-Stamp F. No. 33/70/86-ST]

का. आ. 1891.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन.ए. द्वारा उक्त शुल्क को माफ करती है, जो पंजाब वित्त निगम, चण्डीगढ़ द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र 4 करोड़ रुपये के अकिन मूल्य के 100-100 रुपये के 15 प्रतिशत असम्पत्तिवर्तनीय आरक्षित ऋण-पत्रों के 1 श्रृंखला पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी है।

[संख्या 30/87 स्टाम्प का. सं 33/21/87 वि. कर]

श्री. आर. मेहमी, धवर सचिव

S.O. 1891.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the National Engineering Industries Limited, Calcutta to pay consolidated stamp duty of rupees three lakhs only chargeable on account of the stamp duty on 15 per cent Non-convertible secured debentures of Rs. 100 each (I series) of the face value of rupees four crores only to be issued by the said company.

[No. 30/87-Stamp F. No. 33/21/87-ST]

B. R. MEHMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1987

का. आ. 1892.—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 3 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के प्रयोजनार्थ श्री एल. के. मिश्रा को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त करती है, जिनका पदाभिधान विशेष प्रवर्तन

615 GI/87—2

निदेशक होगा और उक्त अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें तख्तीन बनाए गए किसी नियम, निदेश या आदेश या उसके उपबंधों में से किसी भी उपबंध (धारा 13, धारा 18 की उपधारा (i) के खंड (क) और धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न के उल्लंघन के मामलों का अधिनिर्णय करने के लिए सशक्त करती है।

[फा. सं. 174/13/87-तक. सम. (प्र.)]

New Delhi, the 10th July, 1987

S.O. 1892.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, read with clause (e) of Section 3 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby appoints Shri L. K. Singhvi to be an officer of Enforcement, with the designation of Special Director of Enforcement, for the purpose of enforcing the provisions of the said Act; and in exercise of the powers conferred by Section 50 of the said Act hereby empowers him to adjudicate cases of contravention of any of the provisions thereof (other than Section 13, clause (a) of Sub-section (1) and Section 18 and clause (a) of Sub-section (1) of Section 19) or of any rule, direction or order made thereunder.

(F. No. 174/13/87-TC(E))

का. आ. 1893.—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 3 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के प्रयोजनार्थ श्री वृष्ण कान्त को प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त करती है, जिनका पदाभिधान विशेष प्रवर्तन निदेशक होगा और उक्त अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन्हें तख्तीन बनाए गए किसी नियम, निदेश या आदेश या उसके उपबंधों में से किसी भी उपबंध (धारा 13, धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न के उल्लंघन के मामलों का अधिनिर्णय करने के लिए सशक्त करती है।

[फा. सं. 174/12/87-त.म. (प्र.)]

टी. ओ. खाखा, उपसचिव

S.O. 1893.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, read with clause (e) of Section 3 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Central Government hereby appoints Shri Krishna Kant to be an officer of Enforcement, with the designation of Special Director of Enforcement, for the purpose of enforcing the provisions of the said Act; and in exercise of the powers conferred by Section 50 of the said Act hereby empowers him to adjudicate cases of contravention of any of the provisions thereof (other than Section 13, clause (a) of Sub-section (1) of Section 18 and clause (a) of Sub-section (1) of Section 19) or of any rule, direction or order made thereunder.

(F. No. 174/12/87-TC(E))

T. O. KHAKHA, Dy. Secy.

## आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 जून 1987

का.प्रा.1894—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री जे.डी. भोगले को भण्डारा ग्रामीण बैंक, भण्डारा का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 21-5-87 से प्रारम्भ होकर 30-5-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री भोगले अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-11/87-आर आर बी]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 30th June, 1987

S. O. 1894.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri J. D. Bhogle as the Chairman of the Bhandara Gramin Bank, Bhandara and specifies the period commencing on the 21-5-87 and ending with the 30-5-90 as the period for which the said Shri Bhogle shall hold office as Chairman.

[No. F 2-11/87-RRB]

का.प्रा.1895—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री ए.के. गोडबोले को जिनकी धारा II की उपधारा (1) के तहत भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 28-2-87 को समाप्त हो गयी है, 1-3-87 से प्रारम्भ होकर 20-5-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं. एक 2-11/87-आर आर बी]

S.O. 1895.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby re-appoints Shri A. K. Godbole whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 28-2-87 as the Chairman of Bhandara Gramin Bank, Bhandara for a further period commencing from 1-3-87 and ending with 20-5-87.

[No. F. 2-11/87-RRB]

का.प्रा.1896—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एन.आर. माचले को वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-6-87 से प्रारम्भ होकर 30-6-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री माचले अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं. एक 2-19/86-आर आर बी]

S.O. 1896.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri N. R. Machale as the Chairman of the Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnur and specifies the period commencing on the 1-6-87 and ending with the 30-6-90 as the period for which the said Shri Machale shall hold office as Chairman.

[No. F 2-19/86-RRB]

का.प्रा.1897—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एन.पी. राजू को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की पहली अवधि 24-6-86 का समाप्त हो गयी है, 25-6-86 से प्रारम्भ होकर 31-5-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[संख्या एक 2-19/86-आर आर बी]

S.O. 1897.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby re-appoints Shri M. P. Raju whose earlier tenure of three years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 24-6-86 as the Chairman of Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarnur for a further period commencing from 25-6-86 and ending with 31-5-87.

[No. F 2-19/86-RRB]

का.प्रा.1898—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री राम अवतार सिंह को श्रावस्ती ग्रामीण बैंक, ब्रह्मपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-6-87 से प्रारम्भ होकर 30-6-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री राम अवतार सिंह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-27/87-आर आर बी]

S.O. 1898.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri Ram Avtar Singh as the Chairman of the Sravasthi Gramin Bank, Brahmur and specifies the period commencing on the 1-6-87 and ending with the 30-6-90 as the period for which the said Shri Ram Avtar Singh shall hold office as Chairman.

[No. F 2-27/87-RRB]

का.प्रा.1899—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन.आर. के हेब्बर को बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 7-6-87 से प्रारम्भ होकर 30-6-90 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री हेब्बर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक 2-13/87-आर आर बी]

S.O. 1899.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri A. R. K. Hebbar as the Chairman of the Bijapur Gramina Bank, Bijapur and specifies the period commencing on the 7-6-87 and ending with the 30-6-90 as the period for which the said Shri Hebbar shall hold office as Chairman.

[No. F. 2-13/87-RRB]

का.प्रा.1900—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री के.पी. एकवती को जिनकी धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की चार वर्ष की पहली अवधि 31-3-87 को समाप्त हो गयी

है, 1-4-87 से प्रारम्भ होकर 6-6-87 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए जन बैंक का पुनः प्रष्यक्त नियुक्त करती है।

[संख्या एफ. 2-13/87-आर आर बी]

प्रवीण कुमार तेजयान, अवर सचिव

S.O. 1900—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby re-appoints Shri K. V. Shanbahogue whose earlier tenure of four years appointment under sub-section (1) of section 11 had expired on 31-3-87 as the Chairman of Bijapur Grammeena Bank, Bijapur for a further period commencing from 1-4-87 and ending with 6-6-87.

[No. F. 2-13/87-RRB]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1987

का. आ. 1901—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबन्ध जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि., जूनागढ़, गुजरात पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[एफ सं. 8-1/87 ए. सी.]

New Delhi, the 14th July, 1987

S.O. 1901.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Junagadh District Central Cooperative Bank Ltd., Junagadh, Gujarat from the date of publication of this notification in the official Gazette to 31 December, 1989.

[F. No. 8-1/87-AC]

का. आ. 1902—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबन्ध चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि., चंडीगढ़ पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 24 मई, 1988 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[एफ संख्या 8/1/87 ए. सी.]

के. पी. पाण्डेयन, अवर सचिव

S.O. 1902.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Chandigarh State Co-operative Bank Ltd., Chandigarh from the date of publication of this notification in the official Gazette to 24 May, 1988.

[F. No. 8-1/87-AC]

K. P. PANDIAN, Under Secy.

आयकर आयुक्त

पश्चिम बंगाल VII

कलकत्ता, 21 मई, 1987

का. आ. 1903—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 226 की उप-धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल एतद्वारा निम्नलिखित आयकर अधिकारियों को उनके क्षेत्राधीन सभी निर्धारित का बकाया कर वसूल करने के लिये आयकर अधिनियम 1961 की तृतीय अनुसूची में तथा निर्धारित ढंग से उनके चल सम्पत्ति का करस्वम् और विक्रय करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:

- 1 जिला—IIIए, कलकत्ता के आ. अ., ए. बी., सी, डी, ई एफ जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन और ओ वार्ड,
- 2 सी. एस. सी. कलकत्ता के आ. अ., —ए, बी, सी और डी-वार्ड।
- 3 जिला—Vए, कलकत्ता के आ. अ., ए, बी, सी, डी, ई, एफ जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी वार्ड।
- 4 स्पेशल सर्कल—V कलकत्ता के आ. अ. ए. बी. और सी, वार्ड
- 5 न्यास सर्कल, कलकत्ता के आ. अ., ए, बी, सी, डी और ई वार्ड।
- 6 सी ए. सर्कल, कलकत्ता के आ. आ. "ए" और आ. आ. "बी" वार्ड।

[सं. रिकवरी/पं. VIII/87-88]

डी. के. राय, आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल VII, कलकत्ता।

#### COMMISSIONER OF INCOME TAX

#### WEST BENGAL-VII

Calcutta, the 21st May, 1987

S.O. 1903.—In exercise of the power conferred on me under Sub-section 5 of the section 226 of the I.T. Act, 1961, I Commissioner of income-tax, West Bengal-VII, hereby authorise each of the following Income-tax Officers to recover the arrears of tax due from all assesses under his jurisdiction by distraint and sale of his movable property in the manner laid down in the third schedule of the I.T. Act, 1961 :

1. I.T.Os A B C D E F G H I J K L M N and O words of Dist. IIIA. Calcutta.
2. I.T.Os A B C and D words of C.S.C. Calcutta.
3. I.T.Os A B C D E F G H I J K L M N O and P words of Dist VA, Calcutta.
4. I.T.Os A B and C words of Special Circle-V, Calcutta.
5. I.T.Os A B C D and E words of Trust Circle, Calcutta.
6. I.T.O. 'A' and I.T.O. 'B' Words of C.A Circle, Calcutta

[No. Recovery/WB-VII/87-88]

D. K. ROY, Commissioner of Income-Tax,  
WB-VIII, Cal.

#### वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1987

का. आ. 1904—मैसर्स रेयन इलेक्ट्रोनिक्स को—के अन्तर्गत का आयात करने

रु. 8, 82,000/—(रुपये आठ लाख बयासी हजार) का एक आयात लाईसेंस संख्या पी/एस/1984648 तिथि 17/2/87 दिया गया था।

## MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports &amp; Exports)

New Delhi, the 7th July, 1987

फर्म द्वारा उपर्युक्त लाईसेंस की सीमा शुल्क मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति की भांज इस आधार पर की गई है कि मूल सीमा शुल्क विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह भी कहा गया है कि लाईसेंस की सीमा शुल्क मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास दर्ज न कराई गई थी, अतः इस प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के मूल्य को को बिस्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया है।

S.O. 1904.— M/s. Ryan Electronics, Bombay-18 were granted an import licence No. P/S/1984648/C/XX/H/03/87 dated 17-2-1987 for Rs 8,82,000 only (Rupees Eight Lakhs and eighty two thousand only) for import of Seconds/Second Grades/Defective Cuttings/Sheets C-OILS Strips etc under F.F.E.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs/Ex. Control purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs/Exchange Control purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It is further been stated that the Customs/Ex. Control purposes copy of the licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of Customs Purposes copy has not been utilised at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public Bombay. I am accordingly satisfied that the original Customs/Ex. Control purposes copy of import licence No. P/S/1984648/C/XX/H/03/87 dated 17-2-87 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs/Ex. Control Purposes copy No. P/S/1984648 dt. 17-2-87 issued to M/s. Ryan Electronics, Bombay is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs/Ex. Control Purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[No. Suppl/S-64/SSI/87/SLS/2626/357]

P. MOHAN, Dy. Chief Controller of Imp. and Exp.

2. लाईसेंसधारी ने अपने तर्कों के समर्थन में नोटरी पब्लिक बम्बई के समक्ष विधिवत शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं तबतुसार संतुष्ट हूँ कि आयात लाईसेंस सं. पी/एस/1984648 तारीख 17/2/87 की मूल सीमा शुल्क मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति फर्म द्वारा खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है। यथा सशोधित आयात नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(ग)(ग) के अधीन प्रदान अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्स रेयन इलेक्ट्रॉनिक्स को दी गई उपर्युक्त मूल सीमा शुल्क विनियम नियंत्रण प्रति को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. उपर्युक्त लाईसेंस की सीमा शुल्क विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि पाटी को अलग से जारी की जा रही है।

[छं. एस यू पी पी एल/एस-64 एस एस आई/87/एस एल ए ]

पी. मोहन, उपमुख्य नियंत्रक,

आयात एवं निर्यात

## ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1987

का.आ. 1905:—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें उपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त भूमि में कोयला के पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में संबंधित रेखांक सं. बी.सी. सी.एल./ई.डी./86/60 तारीख 2 सितंबर, 1986 का निरीक्षक उपायुक्त धनबाद (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, II काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में या निदेशक (तकनीकी) परियोजना भारत कोकिंग कोल लि., कोयला भवन, डाकघर कोयला नगर जिला धनबाद (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि से हितवद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्ट और अन्य दस्तावेजों का कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) नियम, 1957 के नियम 5 की अपेक्षा अनुसार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तब्बे दिन के भीतर तकनीकी निदेशक (परियोजना), भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद को परिदान करेगा।

## अनुसूची

सीतानाला यू/जी ब्लॉक

(झरिया कोयला क्षेत्र)

अनन्य अधिकार		पूर्वोक्षण के लिए अधिसूचित की जाने वाली भूमि				
क्रम सं.	ग्राम	थाना सं.	थाना	जिला	क्षेत्र एकड़ में	टिप्पणियां
1.	कुलसारा	228	चास (चंदन कियारी)	धनबाद	56.32 एकड़	भाग
2.	सीतानाला	229	यथोक्त	यथोक्त	20.48 एकड़	भाग
3.	बनसारा	233	यथोक्त	यथोक्त	184.32 एकड़	भाग
4.	सिम्बाबुडीह	227	यथोक्त	यथोक्त	12.80 एकड़	भाग
5.	पाथरगोरा	231	यथोक्त	यथोक्त	7.68 एकड़	भाग

कुल क्षेत्र : 281.60 एकड़ (लगभग)

या 114.00 हेक्टर (लगभग)

## यू/जी के अधीन सीतानाला का सीमा वर्णन

- क-ख रेखा ग्राम सिम्बाबुडीह, सीतानाला से होकर जाती है और ग्राम कुलसारा पाथरगोरा की उत्तरी सीमा के साथ-साथ चलती हुई बिन्दु "ख" से मिलती है।
- ख-ग रेखा पाथरगोरा ग्राम से होकर जाती है और बिन्दु "ग" से मिलती है।
- ग-घ रेखा बनसारा ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और पाथरगोरा ग्राम से गुजरती है तथा "घ" बिन्दु से मिलती है।
- घ-ङ रेखा ग्राम कुलसारा की दक्षिण पूर्वी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु "ङ" से मिलती है।
- ङ-च रेखा ग्राम बनसारा की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु "च" से मिलती है।
- च-छ रेखा ग्राम बनसारा की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु "छ" से मिलती है।
- छ-क रेखा बनसारा, कुलसारा और सिम्बाबुडीह ग्रामों से होकर जाती है और बिन्दु "क" से मिलती है।

[नं. 43015/18/86-सी.ए.]

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 10th July, 1987

S.O. 1905.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule here to annexed.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of the intention to prospect for coal therein.

The Plan No.BCCL/ED/86/60 dated the 2nd September, 1986 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner (Bihar) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, or in the office of the Director (Technical) Projects, Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhavan, Post Office Koyla Nagar, District Dhanbad (Bihar).

Any person interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in Sub-section (7) of section 13 of the said Act, to the Director Technical (Projects), Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad within ninety days from the date of the publication of the notification in the Gazette of India as required by rule 5 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Rules, 1957.

## SCHEDULE

Sitnala Under Ground Block

(Jharia Coalfield)

Mining rights

Showing land to be notified for prospecting

Serial number	Village	Thana number	Thana	District	Area in acres	Remarks
1.	Kulsara	228	Chas (Chandan Kiyari	Dhanabad	56.32 acres	Part
2.	Sitanala	229	—do—	Dhanabad	20.48 "	Part
3.	Bansara	233	—do—	Dhanabad	184.32 "	Part
4.	Sibbabudih	227	—do—	Dhanabad	12.80 "	Part
5.	Pathargora	231	—do—	Dhanabad	7.68 "	Part

Total Area 281.60 acres (approximately)

or

114.00 hectares (approximately)

## Boundary Description of Sitanala U/G Block

- A—B Line passes through the Village Sibbabudih, Sitanala and the along Northern boundary of village Kulsara, Pathargora and meets at point "B".
- B—C Line passes through the village Pathargora and meets at point "C".
- C—D Line passes along the Eastern boundary of village Bansara and through the village Pathargora and meets at point "D".
- D—E Line passes along the South Eastern boundary of village Bansara and meets at point "E".
- E—F Line passes along the Southern boundary of village Bansara and meets at point "F".
- F—G Line passes along the Western boundary of village Bansara and meets at point "G".
- G—A Line passes through the villages Bansara, Kulsara and Sibbabudih and meets at point "A".

[F. No. 43015/18/86—CA]

का.भा. 1906—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 18 जनवरी, 1986, भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. 158 तारीख 26 दिसम्बर, 1985 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 90.00 एकड़ (लगभग) या 36.42 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 90.00 एकड़ (लगभग) या 36.42 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 90.00 एकड़ (लगभग) या 36.42 हेक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण उपायुक्त गिरिडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1—काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची  
पश्चिम धोरी-विस्तारण -1  
ब्लाक पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र  
जिला गिरिडीह (बिहार)  
ड्राइंग सं. राजस्व /23/86  
तारीख:—26-5-1986  
(अर्जित की गई भूमि)

गभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम	थाना	थाना सं.	जिला	क्षेत्र	ट्रिप्लिगियां
1.	एमलो	बर्मो	64	गिरिडीह	90.00	भाग

कुल : क्षेत्र 90 00 एकड़ (लगभग)  
या 36.42 हेक्टर (लगभग)

एमलो ग्राम में अर्जित किए गए प्लॉट सं.

23(भाग), 25(भाग), 26(भाग), 28(भाग), 32(भाग), 33(भाग), 47(भाग), 48 से 51, 52(भाग), 53(भाग), 55(भाग), 56(भाग), 57 से 61, 62(भाग), 91(भाग), और 135 (भाग)

सीमा वर्णन .

- क—रेखा, एमलो और कारे ग्रामों की सम्मिलित सीमा के भाग के साथ-साथ जाती है (जो कारे ब्लाक विस्तारण की पूर्वी सीमा के साथ साथ सम्मिलित सीमा का भाग बनाती है) ।
- ख—रेखा, एमलो ग्राम से होकर जाती है (जो धोरी विस्तारण की उत्तरी सीमा के साथ सम्मिलित सीमा बनाती है) ।
- ग—रेखा, एमलो ग्राम के प्लॉट सं. 135, 91 और 47 में से होकर जाती है ।
- घ—रेखा, एमलो ग्राम के प्लॉट सं. 47, 62, 55, 56, 53, 52, 32, 28, 26, 25, 23 और 33 में से होकर जाती है और बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं. 43019/14/84-सी.ए.]

समय सिंह, अवर सचिव

S.O. 1906.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 158 dated the 26th December, 1985, published in the Gazette of India part II section 3, sub-section (ii) dated the 18th January, 1986, under sub-section (1) section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands measuring 90 00 acres (approximately) or 36.42 hectares (approximately) in the locality specified in the schedule appended to that notification.

And where-as the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Government.

And where as the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Bihar, is satisfied that the lands measuring 90.00 acres (approximately) or 36.42 hectares (approximately) described in the schedule appended hereto should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 90.00 acres or 36.42 hectares (approximately) described in the said schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the office of the Coal Controller, I—Council House Street, Calcutta or in the office of the Central Coalfields Limited (Revenue section) Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

## SCHEDULE

All Rights

West Dhori Extension-Block -I

East Bokaro Coalfield

Drp.No.Rev/23/86

Distt. Giridih (Bihar)

Dated : 26-5-86

(Showing Lands acquired)

Serial number	Village	Thana	Thana Number	District	Area	Remarks
1.	Emlo	Bermo	64	Giridih	90.00	Part
Total area :— 90.00 acres (approximately) or 36.42 hectares (approximately)						

Plot numbers acquired in village Emlo :—

23(Part), 25(Part), 26(part), 28(Part), 32(Part), 33(Part), 47(Part), 48 to 51, 52(Part), 53(Part), 55(Part), 56(Part), 57 to 61, 62(Part), 91(Part), 135(Part).

Boundary description :—

- A—B Line passes along the part common boundary of village Emlo & Karo (Which forms part common boundary with the Eastern boundary of Karo Block Extn.).
- B—C Line passes through village Emlo (Which forms common boundary with the Northern boundary Dhori Extn.)
- C—D Line passes through plot numbers 135, 91 & 47 in village Emlo.
- D—A Line passes through plot numbers 47, 62, 55, 56, 53, 52, 32, 28, 26, 25, 23, & 33 in village Emlo and meets at point 'A'.

[No 43019/14/84—CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1987

का. भा. 1907 :—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में और बिहार सरकार के परामर्श से, डा. सूर्य प्रसाद सिंह, निदेशक स्वास्थ्य सेवा, पटना को, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य नामनिर्दिष्ट किया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. भा. 138 तारीख 9 जनवरी, 1960 (संख्या 5/13/59 एम आई) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट शीर्ष के अधीन क्रम संख्या 13 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“डा. सूर्य प्रसाद सिंह,  
निदेशक, स्वास्थ्य सेवा,  
बिहार सरकार, पटना”

[सं. की. 11013/14/87 एम ई (पी)]

भार. श्रीविज्ञान, प्रवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 24th June, 1987

S.O. 1907.—Whereas in pursuance of the provision of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and in consultation with Government of Bihar, Dr. Surya Prasad Singh, Director of Health Services, Patna, have nominated to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this notification.

Now, therefore, in pursuance of sub section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Health, No. S.O. 138 (No. 5-13/59-MI) dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading “Nominated under clause (a) of sub-section (1) of section 3” against S. No. 13 of the following entries may be inserted, namely :—

13. “Shri Dr. Surya Prasad Singh,  
Director of Health Services,  
Government of Bihar,  
Patna.

[No. V. 11013/14/87-ME(P)]

R. SRINIVASAN, Under Secy.



नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1987

का. भा. 1908—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसरण में, डा. आर. के. केसवानी को, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक की कोर्ट द्वारा इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. भा. 138(सं. 5-13/59 एम ई) तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के नीचे क्रम सं. 54 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्—

“54. डॉ. आर. के. केसवानी,  
प्रोफेसर और अध्यक्ष,  
शल्य चिकित्सा विभाग,  
मेडिकल कालेज,  
रोहतक (हरियाणा)”

[संख्या वी. 11013/20/87-एम.ई. (पी.)]

आर. श्रीनिवासन, अवसर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 1987

S.O. 1908.—Whereas in pursuance of the provision of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. R. K. Keswani, has been elected by the Court of Maharshi Dayanand University Rohtak to be a member of the Medical Council of India with effect from the date of issue of this Notification.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Govt. of India in the late Ministry of Health, No. S.O. 138 (No. 5-13/59-MI), dated the 9th January, 1960 namely :—

In the said notification, under the heading “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3” for serial number 54 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“54. Dr. R. K. Keswani,

Prof. &amp; Head, Deptt. of Surgery,

Medical College,

ROHTAK (Haryana)”.

[No. V. 11013/20/87-ME(P)]

R. SRINIVASAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1987

का. भा. 1909.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 615 G of I/87—3

के निर्वहणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

1. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली
3. केन्द्रीय आयुर्वेद एवं मिश्र अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
4. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।

[संख्या .ई. 11012/6/87 रा. भा. कार्य.]

पी. के. मेहरोत्रा, संयुक्त सचिव,

New Delhi, the 3rd July, 1987

S.O. 1909—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the Ministry of Health and Family Welfare, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi;

1. Indian Council of Medical Research, New Delhi.
2. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi.
3. Central Council of Research in Ayurveda & Siddha, New Delhi.
4. Central Council of Indian Medicine, New Delhi.
5. National Institute of Ayurveda, Jaipur.

[No. E. 11012/6/87-OLI]

P. K. MEHROTRA, Jt Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 1987

का० भा० 1910:—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान, (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोके दो गई सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रयोगों को बाधन भानों अधिकारिता की स्थानीय समितियों के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उनके अधीन सम्पदा अधिकारों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग प्रारम्भ करवाये जाने का पालन करेंगे:—

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों के प्रयोग और स्थानीय अधिकारिता को नोकाए
1	2
1. भारत रिफ़्यूजीज़ लिमिटेड	भारत रिफ़्यूजीज़ लिमिटेड के परि-सर या उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उनके द्वारा अधिगृहीत या उनके और से अधिगृहीत परिवार जो निम्नलिखित स्थान पर स्थित हैं और जो उनके आने अने प्रशासनिक नियंत्रण में हैं:—
प्रबंधक (प्रशासन/प्रबंधक कार्मिक)	(1) मुंबयान, बाकरो स्टेल मिटो-827001 जिला धनबाद, बिहार।

1	2
उपप्रबंधक (अधिक और प्रशासन) कार्मिक अधिकारी	(2) भंडारीडाह रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र, झाकबर भंडारीडाह— 829132 जिला गिरिडीह, बिहार।
कार्मिक अधिकारी	(3) रांची रोड रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र, झाकबर, राँ 829117 जिला हजारीबाग (बिहार)
प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) उप प्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन)	(4) सिलई रिफ्रेक्ट्रीज संयंत्र झाकबर सैदाई 490001 सरौड़ जिला मुर्गा, मध्यप्रदेश
31. इंडिया फायर ब्रिक्स एंड इन्सु- लेशन कम्पनी लिमिटेड (भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कम्पनी) 1. विधि अधिकारी	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इन्सु- लेशन कम्पनी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उसके द्वारा अधिगृहीत या उसकी ओर से लिए गए परिसर और जो उनके प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

[सं. 4 (18)/86 आर. एन. II]

ए. एन. खन्ने, अवर सचिव

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 24th June, 1987

S.O. 1910—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (1) of the Table below, being officers equivalent in rank to a gazetted officer of Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public Premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
I. BHARAT REFRACTORIES LIMITED	Premises belonging to or taken on lease or requisitioned by or on behalf of Bharat Refractories Limited and which are under their respective administrative control situated at :—
Manager (Administration)/Manager (Personnel)	(1) Head Office, Bokaro Steel City-827001, Distt. Dhanbad, Bihar.

1	2
Deputy Manager (P&A)/Personnel Officer.	(2) Bhanadaridah Refractories Plant, P.O. Bhanadaridah-829132, Distt. Giridih, Bihar.
Personnel Officer	(3) Ranchi Road Refractories Plant, P.O. Maran-829117, Dist. Hazaribagh (Bihar).
Manager (P&T)/Deputy Manager (P&A).	4. Bhilai Refractories Plant, P.O. Newal-490001, Marauda, Dist. Durg, Madhya Pradesh.
II. INDIA FIRE- Premises belonging to or taken on BRICKS & INSULATION CO. behalf of India Firebricks & Insulation Company Limited and which DIARY OF BRL). are under their administrative control.	
1. Law Officer	
[No. 4(18)/86-RM-II] A.N. KHALE, Under Secy.	

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1987

का. आ. 1911—इस विभाग की यथा संशोधित दिनांक 13 जून, 1983 की अधिसूचना संख्या एफ. 13-1/81-डी-1 (एम. पी.) का एतद्वारा आंशिक तौर पर निम्नलिखित और संशोधित किया जाता है :

“क्रम संख्या 22 पर श्री एस. के. चतुर्वेदी का नाम श्री माता प्रसाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए”।

[सं. एफ. 13-15/87-एस.पी.-4]

रमेश कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Deptt. of Y. A. &amp; Sports)

New Delhi, the 7th July, 1987

S.O. 1911.—This Department's notification No. F. 13-1/81-D. I(SP) dated 13th June, 1983 as modified is hereby further partially modified as follow :

“At Sl. No. 22, the name of Shri S. K. Chaturvedi may please be substituted by Shri Mata Prasad”.

[F. No. 13-15/87-S.P.-IV]

RAMESH KUMAR, Under Secy.

पर्यावरण और वन मंत्रालय  
(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

का.आ. 1912:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अधीन निम्नलिखित कार्यालयों, जिसके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है:

1. मरू प्रादेशिक शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, जोधपुर,
2. केन्द्रीय प्रादेशिक शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, जबलपुर,
3. गंगा समभूमि प्रादेशिक शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, पटना,
4. उच्च उच्छाय प्राणि सर्वेक्षण केन्द्र, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, सोलन,
5. पश्चिमी प्रादेशिक शाखा, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, पुणे,
6. उत्तर प्रादेशिक केन्द्र, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, देहरादून।

[सं. ई-11011/18/85-का.हिन्दी-II]

हरे लाल, अवसर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS  
(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 6th July, 1987

S.O. 1912.—In pursuance of sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Department of Environment, Forests & Wildlife, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi:—

1. Desert Regional Station, Zoological Survey of India, Jodhpur.
2. Central Regional Station, Zoological Survey of India, Jabalpur.
3. Gangetic Plains Regional Station, Zoological Survey of India, Patna.
4. High Altitude Zoological Field Station, Zoological Survey of India, Solan.
5. Western Regional Station, Zoological Survey of India, Pune.
6. Northern Regional Station, Zoological Survey of India, Dehradun.

(No. E-11011/18/85-PH II)

HAREY LAL, Under Secy.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

का० आ० 1913:—केन्द्रीय सरकार, नाविक अधिव्य निधि स्कीम, 1966 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (1) के साथ पठित नाविक अधिव्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, आई एन ए ए उप-समिति (फ्लोटिंग स्टाफ) कलकत्ता, को अध्यक्ष, कलकत्ता लाइनर्स कॉन्फरेंस (क्रूज), कलकत्ता के स्थान पर नाविक अधिव्य निधि न्यायी बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, जल-भूतल

परिवहन विभाग (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का० आ० 5757, दि० 28-12-1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 4 और उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी अर्थात्:—

“5 अध्यक्ष,

आई एन ए ए उप-समिति जहाजों मालिकों  
(फ्लोटिंग स्टाफ) कलकत्ता।” के प्रतिनिधि।

[फाइल नं० एम० डब्ल्यू०/एम० डब्ल्यू०/एम०—(30)/82-एम०टी०]

जे० सी० पन्त, अवसर सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Shipping Wing)

New Delhi, the 6th July, 1987

S.O. 1913.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby appoints the Chairman, INSA Sub-Committee (Floating Staff), Calcutta, as Member of the Board of Trustees of the Seamen's Provident Fund in place of the Chairman, Calcutta Liners' Conference (Crews), Calcutta and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Transport, Department of Surface Transport (Shipping Wing) No. S.O. 5757, dated 28-12-1985, namely:—

In the said Notification, for serial number 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

- “5. The Chairman, Standing  
INSA Sub-Committee (Floating Representative.”  
Staff), Calcutta.

[File No. SW/MWS(30)/82-MT]

J. C. PANT, Under Secy.

## (श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1987

का. भा. 1914 :—बम्बई डाक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) स्कीम, 1956 को संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित स्कीम का प्रारूप, जिसे कि केन्द्रीय सरकार डाक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तैयार करने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा इसमें प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त उप धारा की आवश्यकतानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि इस प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अथवा इस तारीख से 45 दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के संदर्भ में ऊपर निर्दिष्ट अवधि से पूर्व किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## मसौदा स्कीम

1 इस स्कीम की बम्बई डाक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) (संशोधन) स्कीम, 1987 कहा जाए।

2. बम्बई डाक वर्कर्स (रोजगार का विनियम) स्कीम, 1956 में खंड 29 के उपखंड 2 के मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मव को रखा जाए, अर्थात्—

“विशेष परिस्थितियों में, अध्यक्ष मद (क), (ख) और (ग) के अन्तर्गत प्रतिबन्धों पर आवश्यकतानुसार छूट दे सकता है।”

[फा. सं. एल बी-16016/3/86-एल IV]

बी. शंकरलिंगम, निदेशक

(Labour Division)

New Delhi, the 16th July, 1987

S.O. 1914.—The following draft of a Scheme further to amend the Bombay Dock Workers' (Regulation of Employment) Scheme, 1956 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections/suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government.

## DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Bombay Dock Workers' (Regulation of Employment) (Amendment) Scheme, 1987.

2. In the Bombay Dock Worker's (Regulation of Employment) Scheme, 1956 for item (d) of sub-clause 2 of clause 29, the following item shall be substituted, namely :—

“In special circumstances, the Chairman may relax restrictions under items (a), (b) and (c) to the extent necessary.”

[F. No. LB-16016/3/86-L. IV]  
V. SANKARALINGAM, Director

## शागर विभाग मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1987

का. भा. 1915 :—पवन हंस लिमिटेड (इससे पूर्व भारतीय हेलीकाप्टर निगम) के शापन और संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 38(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, कैप्टन बी. के. भसीन को तत्काल से पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, पवन हंस लिमिटेड के शापन और संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति कैप्टन बी. के. भसीन को तत्काल से और दो वर्ष की अवधि के लिए पवन हंस लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं :

[सं. ए. बी. 13015 /77 /86/एसी]

देव स्वरूप, निदेशक

## MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 8th July, 1987

S.O. 1915.—In exercise of the powers conferred by Article 38(a) of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Limited (formerly known as Helicopter Corporation of India), the President is pleased to appoint Capt. B. K. Bhasin as Director on the Board of Directors of Pawan Hans Limited with immediate effect.

2. Further in exercise of the powers conferred by Article 39 of the Memorandum and Articles of Association of Pawan Hans Limited, the President is pleased to appoint Capt. B. K. Bhasin as part-time Chairman of Pawan Hans Limited for a period of two years with immediate effect.

[No. AV-13015/77/86-AC]  
DEV SWARUP, Director

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1987

का. भा. 1916 :—सिने कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित सारणी के कालम (i) में उल्लिखित तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के उक्त सारणी के कालम (2) में की गई संगत प्रविष्टि में बिनिविष्ट क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती

## सारणी

अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र
1	2
श्री फाईजी मोहम्मद जिला जज, ग्रेड 1, भद्रास, समस्त तमिलनाडु राज्य	

[संख्या जेड-20025/36/86 सी. एल. टी.]

राय कानूनी, सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd July, 1987

S. O. 1916—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981, the Central Government hereby appoints the office of the Government of Tamil Nadu mentioned in column (1) of the table below, to be Presiding Officer for the purposes of the said Act, for the area specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:—

TABLE

Designation of the Officer	Area
Shri Fyze Mohamood, District Judge, Grade I Madras.	Entire State of Tamil Nad

[File No. Z-20025/36/86—C.L.T.]  
RAM KANUGA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1987

का. भा. 1917—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रत्युत्तरण में, केन्द्रीय सरकार, ई. पी. सेवशन, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबन्धन के सम्बन्ध निधोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, प्रत्युत्तरण में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 26 जून, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 6th July, 1987

S.O. 1917.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employer's in relation to the management of EDP section of M/s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th June, 1987.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 DHANBAD**

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 42 of 1982

**PARTIES**

Employers in relation to the management of EDP Section of Messrs Bharat Coking Coal Limited Jealgera, Distt. Dhanbad.

AND

Their Workmen

**PRESENT:**

Shri S. K. Mitra.

Presiding Officer.

**APPEARANCES:**

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workman: None.

STATE: Bihar

INDUSTRY: Coal

Dhanbad, the 17th June, 1987

**AWARD**

The present reference arises out of Order No. L-20012(424) 81-III(A) dated, the 29th/30th, April, 1982 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows—

"Whether the demand of the workman of EDP Section of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Jealgora that Shri M. P. Yadav, Diesel Mechanic should be recategorised and placed in Technical and Supervisory Grade 'C' is justified? If so, to what relief is the said workman entitled?"

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

S. K. MITRA, Presiding Officer

Memorandum of settlement arrived at between the management of BCCL and the workman namely Shri M P Yadav of EDP section Koyla Bhavan Represented by RCMS.

12th Sept. 1986.

**Management**

1. Ashok Mehta,

Dy C. M. (System)

(Union/Workmen).

1. M. P. Yadav

**SHORT RECITAL OF THE CASE**

The Secretary, RCMS raised an Industrial dispute for re-categorisation and placement of Shri M. P. Yadav, Diesel Mech. of CDP Section in Grade C from Grade D on the ground that he has been discharging the job of Gr. C on being transfer of one Shri S. R. Mishra, Foreman (Mech.) w.e.f. 16-9-82. The conciliation having been failed, the matter was referred for adjudication before the CGIT No. 1 Dhanbad which was numbered as Re. No. 42/82 while the matter was referred for adjudication before the CGIT No. Dhanbad the union/workman approached the management for its amicable settlement. The matter having been discussed on several occasions and ultimately with a view to maintain industrial peace and harmony it was decided to settle the dispute amicably outside the court on the following terms and conditions —

**Terms and conditions**

1. That his case will be referred to DPC for assessing the merit/suitability for the said job and on getting the recommendation of the DPC the concerned workman will be promoted in Gr. C as the asstt. Foreman.
2. That it is agreed that the DPC will be held and promotion order issued within 15 days of Signing this settlement.

3. That since the matter has been settled amicably the question of payment of any back wages, arrears whatever prior to the date of his promotion in Grade C does not arise.
4. That the promotion of Shri Yadav in Grade C will come into effect from the date of settlement.
5. That the parties have agreed to jointly file the copy of settlement before the Presiding Officer, CGIT No. 1 Dhanbad requesting for holding the terms of reference as fair and proper and passed the Award in terms of settlement.
6. That the settlement shall be registered under clause 58(4) of ID Central Rules 1957.

**Management**

Sd/-

1-Aoshk Mehta

Dy. C. M. (System)

**Witness**

(Union/Workman).

Sd/-

Sd/-Manager EDP

1 M. P. Yadav, Diesel Mech.

**Distribution**

1. Chief Labour Commissioner, New Delhi.
2. Secretary, Deptt. of Labour, Govt. of India, New Delhi.
3. RLC(C), Dhanbad.
4. ALC(C) Dhanbad.
5. Person concerned.
6. Office file.

**Seal**CGIT No.  
Dhanbad

Part of the Award  
Adhyasi Adhikari  
CGIT No. 1  
Dhanbad 17-6-1987,

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1987

का.प्र. 1918:—प्रयोगिक विवाद प्रवर्धन, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में, केन्द्रीय सरकार जामादोबा, कोलाररी, मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रबन्धन के सम्बन्ध निषेधकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुसूच में निहित प्रयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रयोगिक प्रवर्धन, संख्या 1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार को 1 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 15th July, 1987

S.O. 1918.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Co. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st July, 1987.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD**

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 20 of 1981

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited.

**AND**

Their Workmen.

**PRESENT :**

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

**APPEARANCES :**

For the Employers—Shri B. Lal, Advocate.

For the Workmen—Shri J. P. Singh, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 24th June, 1987

**AWARD**

The Central Government in the Ministry of Labour has, by Order No. L-20012(103)/81-D.III (A) dated, the 4th May, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of Jamadoba Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, is justified in dismissing Shri N. C. Sarkar, General Mazdoor, from service with effect from 28th April, 1980? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. N. C. Sarkar, a General Mazdoor and concerned workman of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company Limited, was after a domestic enquiry, dismissed from the service with effect from 28-4-1980 by the Agent (Opn.), Jamadoba Group. The subject matter of the present reference is as to whether the said order of dismissal of N. C. Sarkar, General Mazdoor, from the service with effect from 28-4-1980 is justified and, if not, to what relief the said workman is entitled?

3. The management and workman concerned have filed written statements and rejoinder in support of their respective cases.

4. The case of the management is that N. C. Sarkar was working as General Mazdoor (Category-I) at Jamadoba Colliery and he used to be deputed for bringing pay rolls from 3 Pit Time Keeping Section to 4 Incline office from where it used to be sent to Jamshedpur for final processing in computer. Sometime in the month of November, 1979 in course of checking pay rolls, it was detected that abnormal overtime hours had been booked against his name. This arose suspicion of the dealing clerk and, on further checking, it was found that he had regularly got overtime payment from the month of March, 1979 to October, 1979. It was further detected in the course of checking that he used to book overtime hours against his name in the rough attendance pay sheets, also known as Attendance Register or Rough Attendance Register, every month while bringing the pay rolls from 3 Pit Time Keeping Section to 4 Incline Office from where the pay rolls were taken to Jamshedpur for final billing. He also used to resort to scratching of entries made by him against his name after the pay rolls were returned from Jamshedpur after processing. He fraudulently booked overtime against his name in the computerised Rough Attendance Register from March, 1979 to October, 1979 and managed to draw an amount of Rs. 2,317.61. He drew the above amount by manipulating the record of the company and he was in full knowledge that he was drawing excess amount. On being interrogated by Sri B. Ghose the then Asstt. Personnel Officer in presence of S/Shri B. P. Singh, B. Chatterjee, Clerks, Jamadoba Colliery, he admitted his guilt and submitted an application in Bengali accepting his guilt and begged to be excused. Since his misconduct was grave and serious a chargesheet dated 17/19-12-1979 was laid against him and a domestic enquiry into the charge levelled against him was ordered to be held. Sri G. S. Ramesh, Personnel Officer, Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company Limited conducted the enquiry and submitted his report dated 24-3-1980 holding that charges against the concerned workman with regard to dishonesty with company's business which is misconduct under clause 19(2) of the Standing Orders of the Company in respect of Jamadoba Colliery had been established beyond doubt. Consequently he was dismissed from the service of the company with effect from 28-4-1980 on the basis of the enquiry report.

5. The case of the concerned workman, N. C. Sarkar on the other hand, is that though it was not his job as Category-I Mazdoor he was made to carry the Attendance Register from 3 Pit Time Keeping Section to which he was attached to 4 Incline Office. But since he was not that much literate,

he was not aware of the documents which were being given to him, he was not aware also if the documents used to be sent to Jamshedpur for final processing. According to prescribed procedure for entitlement of overtime it is impossible to book overtime in the Rough Attendance Register without the supporting slips duly countersigned by the office concerned. He denied that he booked overtime against his name in the Rough Attendance Pay Sheets every month while bringing the pay rolls from 3 Pit Time Keeping to 4 Incline Section; he denied also that he used to get any such entries against his name scratched after pay rolls were returned from Jamshedpur after alleged processing. With regard to the alleged confessional statement he has stated that the said statement was obtained from him under threat by Sri B. Ghose, the then Asstt. Personnel Officer. He contended that the domestic enquiry was not fairly and properly conducted inasmuch as he was not given reasonable opportunity to conduct his defence at the enquiry and that though the misconduct related to alleged manipulation and forgery of certain entries in Rough Attendance Register, these basic registers were withheld by the management and were not shown to him or produced at the enquiry. According to him the chargesheet was also issued by an officer who was not competent to do so and the Enquiry Officer also was not appointed by a competent authority.

6. At the instance of the management the question whether the departmental enquiry was fair and proper or not was decided as a preliminary issue. It was held that the domestic enquiry was not fair and proper. However, the management was permitted to prove the alleged misconduct against the concerned workman by producing fresh evidence before the Tribunal and the workman also was given fresh opportunity to lead evidence contra.

7. The management examined three witnesses more and introduced in evidence a mass of documents which have been marked Ext. M-16 to M-55.

8. The concerned workman did not adduce any evidence.

9. Sri B. Lal, learned Advocate for the management, has submitted that the concerned workman did not deny that he received payment of a sum of Rs. 2,317.61 from March, 1979 to October, 1979 by way of overtime payment from the Company and that he has not stated that he worked overtime between this period beyond four hours. He has further submitted that it was within the special knowledge of the workman that he was not entitled to any payment by way of overtime work beyond four hours and this circumstance along with his confessional statement and the state of entries in the Rough Attendance Register unimpeachably establish the fact that he and he alone manipulated the Rough Attendance Register by booking overtime against his name and scratching the same afterwards. He has submitted also that the act of manipulation of the concerned workman in the Rough Attendance Register in order to get excess payment is an act of dishonesty with respect to the property of the Company and is a misconduct within the meaning of clause 19(2) of the Standing Orders of the Company. He has pointed out that the workman did not take pains to examine himself before this Tribunal and had he done so, transparent truth would have emerged to his detriment.

10. Sri I. P. Singh, learned Advocate for the concerned workman, has submitted that there is no evidence on record to indicate that the concerned workman was attached to 3 Pit Time Keeping Section and hence, according to him, the main brunt of the case of the management against the workman is lost. He has contended that there is no evidence to establish the fact that the concerned workman manipulated the Rough Attendance Register by booking overtime hours against his name therein and scratching the manipulations thereafter. He has criticised the confessional statement and contended that it is a production of coercion, threat, inducement and hoodwinking resorted to by Sri B. Ghose, the then Asstt. Personnel Officer of Jamadoba Colliery. He has submitted that the concerned workman was not under any obligation to examine himself since the evidence on record will buttress the fact of his innocence and militates against his alleged misconduct. He has also submitted that the chargesheet was not issued by a competent person and hence the entire edifice of the case of the management against the concerned workman founders on the ground.

11. The contention of Sri J. P. Singh that there is no evidence on record to indicate that the concerned workman was attached to 3 Pit Time Keeping Section at the relevant time does not rest on any solid basis. The case of the management is that the concerned workman was attached to 3 Pit Time Keeping Section at the relevant time and this has not been denied by the concerned workman in his written statement. On the contrary there is positive statement of the concerned workman in his written statement that he was attached to the Incharge of 3 Pit Time Keeping Section at the relevant time. Hence the contention of Sri J. P. Singh that the concerned workman was not attached to 3 Pit Time Keeping Section at the relevant time is over-ruled.

12. Sri Singh has urged before me that the chargesheet was not issued by a competent person and hence entire edifice of the case of the management against the concerned workman founders on the ground. This contention also is not sustainable inasmuch as the foundation of the case of the management against the concerned workman in the present proceeding is not on the basis of the chargesheet but on the basis of evidence as adduced before this Tribunal with regard to his alleged misconduct. The chargesheet was a foundation and sheet anchor of the domestic enquiry which has been set at naught upon a finding that it was not fair and proper.

13. Sri Singh has endeavoured to meet the criticism of Sri B. Lal, learned Advocate appearing for the management, with regard to non-examination of the workman concerned by submitting that the workman was not under any obligations to examine himself since the evidence on record will buttress the fact of his innocence and militates against his alleged misconduct. The pleadings of the parties arrayed in this reference, the materials available on record and the evidence adduced highlight the case of the concerned workman that he is innocent and that he has not committed any misconduct by resorting to modus operandi as alleged by the management. That being the position I consider that non-examination of the workman is fatal to his case and in that view of the matter the contention of Sri Singh holds water.

14. Now I shall discuss and decide the crux of the present dispute.

It is the irrefragable position that the concerned workman was a General Mazdoor (Category-I) at Jamadoba Colliery and he used to be deputed for bringing pay rolls from 3 Pit Time Keeping Section to 4 Incline Office. It is also the admitted position that he drew a sum of Rs. 2,317.61 by way of overtime work between the period from March, 1979 to October, 1979 without doing any overtime work except for four hours in the month of October, 1979. It is alleged that in order to get excess payment for overtime work the concerned workman used to manipulate Rough Attendance Register while bringing the same from 3 Pit Time Keeping Section to 4 Incline office at Jamadoba and by scratching these records while bringing back these records from 4 Incline office to 3 Pit Time Keeping Section after the pay rolls were processed at Jamshedpur is computer. It appears that he allegedly made confessional statement voluntarily before Sri B. Ghose, the then Asstt. Personnel Officer of Jamadoba Colliery. In the confessional statement (Ext. M-55) the concerned workman has stated that by mistake he booked his name in the overtime column of pay sheets from March, 1979 to September, 1979 while bringing the same from No. 3 to No. 4 Pit and later he scratched through these columns in the pay-sheets. Thus it is seen that no where the concerned workman has admitted that he made any manipulation in the Rough Attendance Registers or Attendance Registers which have been marked Exts. M-16 to M-24. That apart the concerned workman has taken the position that the confessional statement was obtained from him by Sri B. Ghose by resorting to coercion, threat and inducement. Sri B. Ghose figuring as MW-5 has stated that the workman concerned came to his office on his own and penned the confessional statement disclosing that he had committed some mistake for which he wanted to apologise. Sri Ghose denied that he held out any threat or allurement to him to make the confessional statement. It is the case of the management that the concerned workman on being interrogated by Sri Ghose in presence of S/Shri B. P. Singh and B. Chatterjee, Clerks, admitted his guilt and submitted an application accepting his guilt and begged to be excused.

MW-2, Sri B. P. Singh, has stated that B. Ghose sent for the concerned workman who came and Sri Ghose questioned him about the matter whereupon the concerned workman admitted his guilt and begged to be excused. He has further stated that he saw the concerned workman giving something written in Bengali to Sri Ghose. Thus the statement of Sri Ghose that the workman called on him on his own is a travesty of fact. It is not probable for the concerned workman to make confessional statement unless some sort of threat or inducement was held out to him. It is the case of the concerned workman that he was threatened by Sri B. Ghose of police action. It is the further case of the concerned workman that the alleged confessional statement was extracted from him on the promise that no criminal or departmental action would be initiated against him. In view of the circumstances of the case that the concerned workman was sent for by the Asstt. Personnel Officer who questioned him and also in view of the fact that the Asstt. Personnel Officer did not cautioned him before making the alleged confessional statement, I am of the opinion that so called confessional statement is denuded of the element of voluntariness and is not free from inducement. Besides, as I have pointed out above, so called confessional statement does not pin point the document where the alleged manipulation was made.

15. MW-2, B. P. Singh a clerk of Jamadoba Colliery has stated that upon detection of manipulation he met the concerned workman who admitted his guilt and thereupon the witness submitted a written report about the matter to Sri B. Ghose against the concerned workman. But this report has not been produced before this Tribunal. This is suggestive of the fact that the management was groping in the dark as to how the manipulation in the Rough Attendance Register came about, and immediately upon securing so called confessional statement, either by threat or by inducement, the management issued the chargesheet against the concerned workman. It is worthwhile to point out here that the so-called confessional statement is dated 5-12-1979 and the chargesheet was issued against the concerned workman on 17/19-12-1979. There is no vestige of evidence to indicate that between this period the concerned workman was suspended from service. There is also no evidence that even after a prima facie case was established against him he was not suspended from service. Suspension pending domestic enquiry cannot be considered to be punishment even without pay for indefinite period. (1957(T) LIT 17 SC). The action of the management is suggestive of the fact that it was not sure as to who had committed manipulation in the Rough Attendance Register.

16. In the context of the facts and circumstances the evidentiary value of the Rough Attendance Registers (Exts. M-16 to M-24) has got to be considered. Indeed there are writing and scratching of the same in the Rough Attendance Registers for the months of March, 1979 to November, 1979 (Exts. M-16 to M-24) against the name of the concerned workman Sri B. P. Singh (MW-2) has admitted that there are some cuttings and fresh entries in the Rough Attendance Register marked Ext. M-16. He has further admitted that the corrections made in black ink must have been done by the Time Section, but he cannot say who had made it. He further admitted that at page 10 of Ext M-17 there are similar cuttings in black ink in other pages of the register. He has also admitted "cuttings" :

- (i) in Ext. M-18 in respect of overtime against the name of the concerned workman and also against the name of another worker Rohan Mahato ;
- (ii) in Ext. M-19 against the name of the concerned workman in respect of overtime and also in the name of Rajendra Prasad ;
- (iii) in Ext. M-20 against the name of the concerned workman in respect of overtime and also in the name of Anil Sen ;
- (iv) in Ext. M-21 in respect overtime and attendance of the concerned workman and in respect of attendance of Sarion Saw ;
- (v) in Ext. M-22 in respect of overtime of the concerned workman and in respect of attendance of Anil Sen ;
- (vi) in Ext. M-23 in respect of overtime of the concerned workman and also in respect of overtime of Rohan Mahato.

It appears that various corrections have been made in the Rough Attendance Register in respect of different workman in different columns. The management has not explained as to how and why these corrections were made and by whom except in the case of the concerned workman. In order to place reliance on the Rough Attendance Register the management has a duty to explain the entire position which they have not done. In the circumstances the evidentiary value of the Rough Attendance Register is not so sacrosanct as it has been sought to be so by the management.

17. It appears from the evidence of Sri B. P. Singh that the workman who brings the Rough Attendance Register and input forms from the Time Keeping Section to the Accounts Section (4 Incline) waits in the Accounts Section for sometime and from Accounts Section he takes these papers to the Central Accounts Office along with input forms prepared in the Accounts Section of the colliery and from the Central Accounts Office these papers are taken in boxes on Company's vehicle to Jamshedpur accompanied by five Clerks of the Company. It is his further evidence that the concerned workman used to bring these registers from Time Keeping Section to the Accounts Office and that he used to come to the Accounts Office again and take back the Rough Attendance Registers after they were processed at Jamshedpur to the Time Keeping Section. The management has suggested that the manipulations by the concerned workman has been done at two stages :

- (i) while taking Rough Attendance Registers to the Accounts Office he used to book overtime against his name, and
- (ii) scratching the entries with regard to overtime while taking the Rough Attendance Registers back to the Time Keeping Office. But there is yet another possibility of manipulation in the matter when the Rough Attendance Registers were taken from the Central Accounts Office to Jamshedpur office and back when, admittedly, the concerned workman was in no way in the picture.

The management should have instituted an in-depth probe into the matter in order to ascertain as to how and why the entries in the Rough Attendance Registers came about and scratched through and by whom these things were done and at what stage. That not being done by the management a reasonable inference cannot be drawn that it was only the concerned workman who made manipulation against his name in respect of overtime work.

18. Considering the entire matrix of the case and the evidence on record I come to the conclusion that the management has not been able to prove by any device of positive probability that the Rough Attendance Registers were manipulated by the concerned workman only and none else. That being so the allegation of misconduct against him founders on the ground. In these circumstances I come to the inescapable conclusion that the order of dismissal clumped down on the concerned workman was not justified. Accordingly it is ordered that the management of Jamadoba Colliery of M/s Tata Iron and Steel Company Limited Post Office Jamadoba, District Dhanbad was not justified in dismissing Sri N. C. Sarkar, General Mazdoor, from service with effect from 28-4-1980. Sri N. C. Sarkar be reinstated in the service at once with full back wages from the date of dismissal. He is entitled to Rs. 250/- as cost of the present proceedings.

S. K. MITRA, Presiding Officer

[No. L-20012/103/81-D III(A)]

P. V. SREEDHARAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1987

का० प्र० १९१९—केन्द्रीय सरकार, की राय है कि "सारन संतर-राष्ट्रीय विमानचरित्र पात्रिकरण में सेवा" को श्रौचोपिग विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की प्रथम अनुसूची में जोड़ना लोकहित में समीचीन है;



अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 40 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 26 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ती है, अर्थात्:—

"27 भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानतट प्राधिकरण में सेवा"

[एल०-11017/1/87-डी०-1(ए)(i)]

New Delhi, the 8th July, 1987

S.O. 1919.—Whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest to add to the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the 'Service in the International Airports Authority of India'.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby adds the following item to the First Schedule to the said Act, after item 26 thereof, namely:—

"27. Service in the International

Airports Authority of India".

[F. No. S. 11017/1/87-D.I(A)(i)]

का० आ० 1920:—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानतट प्राधिकरण में सेवा को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 27 के अन्तर्गत आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उप खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए छह माह की अवधि तक के लिए तत्काल लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[एल०-11017/1/87-डी०-1(ए)(ii)]

S.O. 1920.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the service in the International Airports Authority of India, which is covered by entry 27 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S. 11017/1/87-D.I(A)(ii)]

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1987

का.आ 1921:—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि पाइराइट्स खनिज उद्योग को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 20 के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम की प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उप-खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 615 GI-87-4

प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से छः माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं. एन-11017/1/80-डी 1 (ए)]

नन्द लाल, अवसर सचिव

New Delhi, the 15th July, 1987

S.O. 1921.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the Pyrites Mining Industry, which are covered by entry 20 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months.

[No. S-11017/1/80-D.I(A)]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1987

का० आ० 1922:—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी दिल्ली के कार्यालय में धर्म मंत्रालय के अवसर सचिव श्री हनु सिंह को 13 जुलाई से 7 अगस्त, 1987 की अवधि तक उत्प्रवास संरक्षी दिल्ली, के समस्त कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[संख्या-ए०-22012/1/86-उत्प्रवास-II]

ए० बी० एस० शर्मा, अवसर सचिव

New Delhi, the 10th July, 1987

S.O. 1922.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Inder Singh, Under Secretary, Ministry of Labour to perform all functions of Protector of Emigrants, Delhi, in the office of the Protector of Emigrants, Delhi during the period from 13th July to 7th August, 1987.

[No. A-22012(1)/86-Emig. II]

A. V. S. SARMA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1987

का. आ. 1923.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व सैण्डून माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट, रांची के प्रबंधन से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 29-6-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 13th July, 1987

S.O. 1923.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Mine Planning & Design Institute Limited, Gondwana Place, Ranchi and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th June, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 352 of 1986

In the matter of industrial dispute under section 10(1)(d)  
of the I.D. Act, 1947.

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Central  
Mine Planning and Design Institute Gondwana,  
Place, Ranchi and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri B. N. Akhauri, Per-  
sonnel Manager.On behalf of the workmen : Shri R. S. Sharma, Ad-  
vocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Mine Planning

Dhanbad, the 19th June, 1987

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their order No. L-24011(3)/86-D.IV(B) dated the 20th November, 1986.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Central Mine Planning & Design Institute Limited Gondwana Place, Ranchi—

(i) in not promoting and publishing the gradewise seniority list/rating of all workmen in each grade and cadre as on 31-12-74 and as on 31st March each year;

(ii) in not promoting S/Shri D. Bengra, R. C. Das, Miss Rahil Lakra, N. K. Palit and S/Shri Abbas Ansari and Simon Kujur to the post of Sr. Clerks against Scheduled Castes and Scheduled Tribes quota with effect from 15-3-85;

(iii) in denying regularisation as Works Supervisor of S/Shri S. R. Rabidas and Ali Hussain as from 1979;  
is justified ? If not, to what relief the workman concerned are entitled ?"

After filing of the W S by the parties a petition was filed on behalf of the five of the concerned workmen along with two others for passing an award in terms of the settlement arrived at between the concerned workman and the management in respect of item No. 2 of the schedule of the order of reference. The parties also filed the memorandum of settlement arrived at between the management and the individual workmen. They also filed affidavit to the effect that although they had originally authorised the General Secretary National Coal Workers Association to sponsor and canvass their case but they have now fully disassociated from the said union. It will also appear that the National Coal Workers Association which had sponsored the industrial dispute has merged with the R.C.M.S. The W S in the case has been filed by the General Secretary of R.C.M.S. and not by the Secretary of National Coal Workers Association. As National Coal Workers Association has no existence of its own and the workmen did not authorise R.C.M.S. to represent their case the settlement between the individual workmen may be accepted as it is for the advantage of the workmen. It will appear from the memorandum of settlement that seven workmen have entered into settlement with the management out of whom only five are concerned workmen in the case and as such the settlement in respect of the five concerned workmen is accepted. An award is accordingly passed in respect of the five workmen S/Shri N. K. Palit, D. Bengra, Abbas Ansari Simon Kujur, Mrs. Rahil Tirkey (who was

formerly Miss Rahil Lakra) in terms of the memorandum of settlement which forms part of the Award as Annexure. The reference is thus partially disposed off, in respect of the above named five concerned workmen.

I. N. SINHA, Presiding Officer  
[No. L-24011(3)/86-D.IV(B)]  
R. K. GUPTA, Desk Officer

## ANNEXURE

Memorandum of settlement arrived at between the management of Central Mine Planning and Design Institute Ltd., Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi and their workmen S/Shri (1) Abu Salik, (2) D. N. Das, (3) N. K. Palit, (4) Simon Kujur, (5) Smt. Rahil Tirkey (formerly Miss Rahil Lakra) (6) S/Shri Abbas Ansari and D. Bengra.

Representing Employer Shri B. N. Akhauri, Person-  
nel Manager, CMPDT, Ranchi.

Representing workmen S/Shri

(2) D. N. Das

(1) Abu Salik

(3) N. K. Palit

(4) Simon Kujur

(5) Smt. Rahil Tirkey  
(formerly Miss Rahil Lakra)

(6) Sri Abbas Ansari

(7) D. Bengra.

## Short recital of the case

The Government of India, Ministry of Labour, vide their Order No. L-240011(3)/86-IV(S) dated 20-11-1986 referred an industrial dispute to the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad for adjudication with the following terms of Reference :

"Whether the action of the Management of Central Mine Planning & Design Institute Limited, Gondwana Place, Ranchi;

(i) in not promoting and publishing the gradewise seniority list/rating of all workmen in each grade and cadre as on 31-12-74 and as on 31st of each year;

(ii) in not promoting S/Shri D. Bengra, R. C. Das, Miss Rahil Lakra, N. K. Palit and S/Shri Abbas Ansari and Simon Kujur to the post of Sr. Clerks against Scheduled Caste and Schedule Tribes quota with effect from 15-3-1984;

(iii) in denying regularisation as Work Supervisor of S/Shri S. R. Rabidas and Ali Hussain as from 1979 is justified if not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

While the issue under reference to the Hon'ble Tribunal is pending S/Shri Abu Salik, D. N. Das, D. Bengra, N. K. Palit, Abbas Ansari, Simon Kujur and Smt. Rahil Tirkey (formerly Miss Rahil Lakra) approached the Management with the request that this matter be negotiated with them and settled. The concerned workmen informed the Management that they had never authorised the National Coal Workers Association or its General Secretary to raise an Industrial Dispute, much less sponsor the same. They have also sworn affidavits to this effect before the Notary Public Ranchi on 25-4-1987 by 6 workmen and Smt. Rahil Tirkey on 27-4-87 stating therein that they had never authorised the General Secretary National Coal Workers Association to sponsor and canvass their case either before the Asst. Labour Commissioner (C), Ranchi or before the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad. The matter was accordingly negotiated between the management and the seven workmen referred above and a settlement has been arrived at between the two parties on 25-4-87 on the following terms :

## Terms of Settlement

1. It is agreed that the concerned workmen will be promoted to the next higher post as indicated against each :

Sl. No.	Name of the workman	Post held at present	Post to which promotion will be given
1.	S/Sri Abu Salik	U.D.C.	Sr. Clerk
2.	" D N Das	A/J. Clerk Gr. I	A/c. Asstt.
3.	" N K Palit	U.D.C.	Sr. Clerk
4.	" Simon Kujur	UDC	Sr. Clerk
5.	" Abbas Ansari	A/c. Clerk Gr. I	Accounts Asstt.
6.	Smt. Rahil Tirkey	U.D.C.	Sr. Clerk
7.	Sri D. Bengra	U.D.C.	Sr. Clerk.

2. That it is agreed that the employees will be promoted as stated in clause 1 above w.e.f. 2-5-1987 and that they will be given seniority w.e.f. 27-4-1987.

3. It is agreed that on account of this settlement, the dispute referred to the Hon'ble Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad (Reference No. 352 of 1986) will stand fully resolved in respect of the seven workmen concerned and that the seven workmen concerned will accordingly submit a petition to the said Hon'ble Tribunal to dispose of the reference with respect to them accordingly.

4. It is agreed that this is an overall settlement between the management and 7 workmen referred above in full and final settlement of all their claims arising out of the afore-said reference.

B. N. AKHAURY,  
Personnel Manager,  
Representing Employer

1. Abu Salik
  2. D. N. Das
  3. N. K. Palit
  4. D. Banghra
  5. Abbas Ansari
  6. Simon Kujur
  7. Smt. Rahil Tirkey
- (representing employees)

Witness :

- 1.
- 2.

Dated this day 1st May, 1987

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1987

का. प्रा. 1924—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी सविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:—

1. मैसर्स को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लि., मागरलोक करवा रायपुर
2. मैसर्स एम पी. डीजल इंजिनियरिंग सर्विस, ग्रेट ईस्टर्न रोड, ओल्ड मोटर स्टैंड, रायपुर और इसकी शाखनीहीड, रायपुर स्थित वर्कशॉप
3. मैसर्स सेंचुरी प्राटोमोबाइल (इन्दौर) 17 नेहरू मार्केट, ए बी रोड, इन्दौर और इसका मेहुता चम्बर, 13 मेथ्यू रोड, बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय
4. मैसर्स एम. पी. स्टेट सीड सर्टीफिकेशन, ए-7 बी डी ए फालोनी, तुलसीनगर भोपाल और इसकी (1) इन्दौर (2) खाजरा (3) टोकमगढ़ (4) रायपुर (5) जबलपुर स्थित शाखाएँ

5. मैसर्स नोबल सोया हाउस लि. ई-7/638 घरेरा कालोनी, माहपुर, भोपाल और इसकी प्लॉट नं. 5 न्यू इन्डस्ट्रीयल एरिया न.-1 मण्डोदीप कस्बा रासयेन स्थित फील्ड्री तथा इस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिकरोली (ई) बम्बई-79 स्थित प्रशासनिक कार्यालय

6. मैसर्स नेशनल इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजिस्ट प्राईवेट लि., 153 जोन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल और इसकी पी टी आई बिल्डिंग, 4 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली स्थित शाखा

7. मैसर्स भारत टेक्स्टाइल, खाजराणा, कोठी के सामने साकेत नगर के पीछे, इन्दौर

8. मैसर्स हेक्सी फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लि., 4 बी, इन्डस्ट्रीयल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस 35019 (21) /87 एस. एस-2]

New Delhi, the 14th July, 1987

S.O. 1924.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Co-operative Marketing Society Limited, Magarlod District Raipur.
2. M/s. M. P. Diesel Engineering Services, Great Eastern Road, Old Motor Stand Raipur, including its workshop at Chandamdi, Raipur.
3. M/s. Century Automobiles (Indore), 17, Nehru Market, A. B. Road, Indore, including its Head Office at Mehta Chambers, 13, Mathew Road, Bombay.
4. M/s. M. P. State Seed Certification, A-7, B.D.A., Colony Tulsinagar, Bhopal, including its branches at (1) Indore (2) Khandwa (3) Tikamgarh (4) Raipur and (5) Jabalpur.
5. M/s. Noble Soya House Limited E. 7/638, Area Colony, Slahpura, Bhopal, including its factory at Plot No. 5, New Industrial Area No. I Mandideep, District Rajen and Administrative Office at Eastern Express Highway, Vikhroli (E) Bombay-79.
6. M/s. National Information Technologies Private Limited, 153 Zone-1 Maharana Pratap Nagar, Bhopal, including its branch at P. T. I. Building 4, Parliament Street, New Delhi-1.
7. M/s. Bharat Textiles, near A Khajirana Kothi Compound Saket Nagar, Indore-1.
8. M/s. Hexo Pharmaceutical Private Limited, 4-B, Industrial Area, Govindpura, Bhopal.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(21)/87-SS. II]

का. भा. 1925.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्न-लिखित स्थापन से सम्बन्धित नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए उक्त अधिनियम के के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस. 35019 (22)/87 एस. एस-2]

ए. के. भट्टारक, अधीक्षक

S.O. 1925.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. मैसर्स स्टैन्डर्ड एंटर प्राइजज सामने एस. टी जेम्स हाथर सैकन्ड्री स्कूल, जियु मंगलौर
2. मैसर्स श्रीमत् एंटर प्राइजज नं. 49/1 प्रथम मंजिल शुभारामा चेतरीरौ, बासवान गुडी, बंगलौर-4
3. मैसर्स पूरक फैब्रीकेटर्स 21/बी-11 स्टेज इन्डस्ट्रीयल एरिया मैसूर-8
4. मैसर्स पी जयरज एण्ड कम्पनी, 19 और 20 बेलवदी इन्डस्ट्रीयल एरिया, मैसूर-186
5. मैसर्स भानु साइंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट कम्पनी, सी-251, 5 क्रॉस इन्डस्ट्रीयल स्टेट, पिनिया, बंगलौर
6. मैसर्स गुरेश इन्डस्ट्रीज आफ पोलीथीन, एम-12 इन्डस्ट्रीयल स्टेट, उद्यम बाग, बेलगांव-8
7. मैसर्स पी पी काउंडरिंग नं. 16 उद्यम बाग, बेलगांव-8
8. मैसर्स पी एण्ड टी कैन्टीन सैन्ट्रल टेलीग्राफ आफिस, बेलगांव-8
9. मैसर्स राहुल प्लास्टिक, प्लॉट नं. एम-36, इन्डस्ट्रीयल स्टेट उद्यम बाग, बेलगांव-8
10. मैसर्स देवी कैमिकल लैबोरी, हास्पिटल रोड कल्लन-1
11. मैसर्स इलेक्ट्रोमिक इन्डस्ट्रीज 6 ए मेन III फेज पीनीया इन्डस्ट्रीयल एरिया बंगलौर-88
12. मैसर्स भास्कर बायो इन्डस्ट्रीज कानवी होनापुर रोड तिवुलगांव गांव कस्बा धरबाड़ और इसका गोकुल रोड हुबली स्थित प्रशासनीक कार्यालय तथा इसका द्वितीय मंजिल सिद्धेश्वर महल स्टेशन रोड हुबली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
13. मैसर्स सोमवारपट तालुक सुबुल्लुद्राह्व लार्ज एरिया मण्टी प्रपज कोपरेटिव सोसाइटी लि. बासवान हाली पोस्ट बाया कृष्णालनगर और इसकी (1) धाबूरकोट (2) यादवनाडू (3) यंगा समुद्र एस पट तालुक स्थित तीन शाखाएं
14. मैसर्स कर्नाटक टेलीकैबलस लि., 28 प्रथम क्रॉस जयलक्ष्मी पुरम मैसूर-12 और इसका नं. 51/9 रिचमण्ड रोड बंगलौर-25 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय तथा सीट महल, 463 डाक्टर एनीबिसेन्ट रोड बम्बई-25 स्थित प्रशासनिक कार्यालय
15. मैसर्स रयुबेल प्रोडियन टूल्स (प्राइवेट) लि. 584 बी एण्ड सी पिनिया इन्डस्ट्रीयल स्टेट 4 फेज पिनिया बंगलौर -58 और इसका नं. 36 शम्पन्जी टैंक रोड बंगलौर-27 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
16. मैसर्स फाइबर सेल्स लि. ए-282, 11 स्टेज पीनीया इन्डस्ट्रीयल स्टेट 4 फेज, पिनिया बंगलौर-58 और इसका 58 एम आई बी सी थन्धेरी पूर्ण बम्बई-93 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय तथा 50/3 ए/2 वैलेंस रोड बंगलौर 52 स्थित प्रशासनिक कार्यालय
17. मैसर्स कर्नाटक बैरिङिंग प्रोड्युक्शन्स बी-123 इन्डस्ट्रीयल स्टेट पीनीया II स्टेज बंगलौर-58 और इसकी (1) बंगलौर-55 (2) बंगलौर-58 (3) मद्रास (4) म्यू विल्सी (5) पूना (6) कलकत्ता स्थित : छ : शाखाएं
18. मैसर्स श्री रामना महाश्वी एकादमी फार दी प्लाहन्ड, नं. 1 बी 3 फेज जे. पी. नगर, बंगलौर-78 और इसकी तिह-मूर्ति हरल डबलमेन्ट सैन्टर नं. 40 कि. मी. स्टीन जाका-संवरा गांव, 16-6-85 मारालावादी हुबली कनकपुरा तालुक बंगलौर स्थित शाखा
19. मैसर्स सुपर ट्रेड्स चिपपदी-101
20. मैसर्स पूणिमा रेस्टोरेन्ट, 449/2 एच सिद्धा रोड विस्सन गांव नं. बंगलौर-27

1. M/s. Standard Enterprises, Opp. St. Johns Higher Secondary School, Jeppu, Mangalore-1.
2. M/s. Srimath Enterprises, No. 49/1, First Floor, Subbarama Chetty Road, Basavangudi, Bangalore-4.
3. M/s. Purak Fabricators, 31/B, II Stage, Industrial Suburb, Mysore.
4. M/s. P. Jayaraj and Company Limited, 19 and 20, Belvadi Industrial Area, Mysore-186.
5. M/s. Bhanu Scientific Instruments Company, C-251, V Cross, Industrial Estate, Peenya, Bangalore-58.
6. M/s. Suresh Industries of Polyethylene, M-12, Industrial Estate, Udyambag, Belgaum-8.
7. M/s. P.P. Foundaries, Plot No. 16, Udyambag, Belgaum-8.
8. M/s. P & T Canteen, Central Telegraph Office, Belgaum-1.
9. M/s. Rahool Plastics, Plot No. M-36, Industrial Estate, Udyambag, Belgaum-8.
10. M/s. Devi Clinical Laboratory Hospital Road, Quilon-1.
11. M/s. Elektromek Industries, 6-A, 6th Main III Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-58.
12. M/s. Bhaskar Bio Industries, Kanavi Honappur Road, Terihal Village, District Dharwad, including its Administrative Office at Gokul Road, Hubli and (2) Registered Office at IInd Floor, Siddesh Bar Mihal Station Road, Hubli.
13. M/s. Somwarpot Taluk Schedule Tribe Large Area Multipurpose Co-operative Society Limited, Basavanahally Post Via Kaushalnagar, including its branches at (1) Abburkatte (2) Yadavanadu (3) Rangasamudra Taluk.
14. M/s. Karnataka Tebecables Limited, 28, I Cross Jayalakshmi Puram Mysore-12, including its Registered Office at No. 51/9 Richmond Road, Bangalore-25 and Administrative Office at Ceat Mahal, 463, Dr. Anne Besant Road, Bombay-25.
15. M/s. Rewdale Precision Tools (Private) Limited, 584, B&C Peenya Industrial Estate, IV Phase, Peenya, Bangalore-58 including its Registered Office at No. 36, Sampangi Tank Road, Bangalore-27.
16. M/s. Fibre Shells Limited, A-282, II stage, Peenya Industrial Estate, Bangalore-58, including its Registered Office at 58, MIDC Andheri East, Bombay-93 and Administrative Office at 50/3A/2, Palace Road, Bangalore-52.
17. M/s. Karnataka Welding Products, B-123, Industrial Estate, Peenya II, Stage, Bangalore-58, including its six Branches at (1) Bangalore-55 (2) Bangalore-58 (3) Madras (4) New Delhi (5) Pune and (6) Calcutta.
18. M/s. Shri Ramana Maharshi Academy for the Blind, No. 1-B, 3rd Phase, J. P. Nagar, Bangalore-78, including its branch at Thirumurthy Rural Development Centre No. 40th K. M. Stone, Jakkasandra Village, 16-6-85 Maralavadi Hobli Kanakapura Taluk, Bangalore.
19. M/s. Super Treads, Chitpady, Udipi-101.
20. M/s. Poornima Restaurant, 449/2, Siddaiah Road,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(22)/87-SS II]

श्री आ. 1926 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए —

1. मैसर्स अमूल टेक्सटाइल, अमना, रोड नं. 2 उद्योग नगर, अमना, जिला सूरत
2. मैसर्स बम्बई फैब्रिक्स, मोदी कम्पाउण्ड रोड नं. 3, उद्योग नगर, अमना, जिला सूरत
3. मैसर्स स्वाति टेक्सटाइल, मोदी कम्पाउण्ड, रोड नं. 3, उद्योग नगर, अमना, जिला सूरत
4. मैसर्स बाबुल टेक्सटाइल, मोदी कम्पाउण्ड उद्योग नगर, रोड नं. 3, अमना, जिला सूरत
5. मैसर्स अमल इन्वस्टमेंट्स, लि., रचना, अपोजिट बम्बई गैरेज, शाही बाग रोड, अहमदाबाद-4
6. मैसर्स फिन्स एण्ड रोड्स, अपोजिट इन्डियन प्राइवेट लि., नरीदा अहमदाबाद
7. मैसर्स पीकवेल जो-1 चित्र अभी एपार्टमेंट लागाऊजर चैम्बरस के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9
8. मैसर्स सरदार बागपत सहकारी मंडली लि. सरदारबाग, बारदोली जिला, सूरत
9. मैसर्स गुजरात बिस्किट फार्मस लि., 6 बी. मजिल मिस्त्री चैम्बरस, बानपुर, अहमदाबाद और इसकी धारा एस. नं. 370 मुक्तिधाम के पास, मान देवी कुच स्थित पैदली
10. मैसर्स सैन्टरल होटल (रैस्टोरेण्ट) रेलवे स्टेशन के सामने, सूरत
11. मैसर्स दिलेश फर्मास्युटिकल प्राइवेट लि., प्लॉट नं. 100/113 जो. आई. डी. सी. नन्वेसरी, जिला बड़ोदा, और इसका यमुना कुज, महावीर कालोमी, राजमहल रोड बड़ोदा-1 स्थित कार्यालय
12. मैसर्स लोटस आयुर्वेद रिसर्च और अस्पताल ट्रस्ट मार्फल सड़क साहित्य बिल्डिंग, भदरा, अहमदाबाद-1 और इसकी आश्रमबाग रोड आश्रमबाग रोड, निर्माण एम. आई. डी. सी. स्टेट लास्मा अहमदाबाद स्थित शाखा।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35019 (23)/87एसएस-2]

S.O. 1926—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Amul Textiles, Udhna Road, No. 2, Udyog Nagar, Udhna District Surat.
2. M/s. Bombay Fabrics, Mody Compound, Road, No. 3, Udyog Nagar, Udhna, District Surat.
3. M/s. Swati Textile, Mody Compound, Road No. 3, Udyog Nagar, Udhna, District Surat.
4. M/s. Babul Textile, Mody Compound, Udyog Nagar Road, No. 3, Udhna, District Surat.

5. M/s. Amal Investments Limited, Rachana, Opposite Bombay Garage Shahi Baug Road, Ahmedabad-4.

6. M/s. Pins and Roads, opposite Indequip Private Limited, Naroda, Ahmedabad

7. M/s. Packwel G. I Chitra Ami Apartments, opposite La Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad-9.

8. M/s. Sardar Bagayat Sahakari Mandli Limited Sardar Baug, Bardoli, District Surat.

9. M/s. Gujarat Wind Farms Limited 6th Floor, Ministry Chambers, Khanpur, Ahmedabad, including its factory at R. S. No. 370, Near Muktidham Mandvi, Kutch.

10. M/s. Central Hotel (Restaurant) opposite Railway Station, Surat.

11. M/s. Dinesh Pharmaceutical (Private) Limited, Nandesari, District Baroda, including its Office at Yamuna Kunj, Mahavir Colony, Raj Mahal Road, Baroda.

12. M/s. Lotus Ayurved Research and Hospital Trust C/o Sastu Sahitya Building Bhadra, Ahmedabad, including its branch namely Akha Akhandanand Ayurvedic Anushadh Nirman N.I.D.C. Estate, Lembha, Ahmedabad

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(23)/87-SS. II]

का. आ 1927 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए —

1. मैसर्स पोपुलर कन्स्ट्रक्शन रोड नं. 4 आजादपुर मैंगो, जमशेदपुर
2. मैसर्स कलिक एण्ड कम्पनी, काबेरी रोड, दाईचोद, शिवामन्दिर के समीप मैंगो, जमशेदपुर
3. मैसर्स सरकार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, 45 ठाकुरबारी रोड, साकची जमशेदपुर
4. मैसर्स विद्युत सदन, 134 अमता लार्डन, साकची बाजार, जमशेदपुर-1
5. मैसर्स आजीय कन्स्ट्रक्शन कम्पनी रामवास बंगला, बिस्तुपुर जमशेदपुर-1
6. मैसर्स युनिक एंटरप्राइज पुरुलिया हाईवे जवाहरनगर, गीतिली मैंगो जमशेदपुर।
7. मैसर्स लक्ष्मी टाकीज, पोस्ट आफिस बीरकुडा, धमबाद।
8. मैसर्स मेनोसपार्क इन्जिनियरिंग इन्स्टीट्यूट, इन्स्टीट्यूट एरिया पटना-13

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस 35019(19)/87 एसएस-2]

S.O. 1927—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Popular Construction, Road No. 4, Azad Nagar, Mango, Jamshedpur-12.

2. M/s. Kalika and Company, Kaberi Road, Daighuttu, Near Shiba Mandir, Mango, Jamshedpur.
3. M/s. Sarkar Construction Company 45, Thakur Bari Road, Sakehi, Jamshedpur.
4. M/s. Bidyut Sadan, 134, Apna Line Sakehi Bazar, Jamshedpur-1.
5. M/s. Ajoy Construction Company, Ramdas Bunglow, Bistupur, Jamshedpur-1.
6. M/s. Unique Enterprise, Purulia, Highway, Jawahar Nagar, "Gutlpi" Mango, Jamshedpur.
7. M/s. Laxmi Talkies, Post Office Chirkunda, District Dhanbad.
8. M/s. Menopak Engineering Industries, Industrial Area, Patna-13.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(19)/87-SS. II]

का. भा. 1928 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारी की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए—

1. मसर्स जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, स्टेडियम सिनेमा के सामने और इसकी जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, स्टेडियम शॉपिंग सेंटर, स्टेडियम ग्राउंड, जोधपुर-19 स्थित शाखा
2. मसर्स सुनील सायनेम लिमिटेड, 17/18 ओल्ड इन्डस्ट्रियल एरिया प्रसन्न और इसकी (1) नई दिल्ली (2) बम्बई (3) कलकत्ता (4) मद्रास (5) अहमदाबाद स्थित पांच शाखाएं।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 को उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस 35019(18)/87 एस एस-2]

ए. के. भट्टराई, सचिव

S.O. 1928.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Jodhpur Nagrik Sahakari Bank Limited, Opposite Stadium Cinema, Jodhpur, including its branch at Jodhpur Nagrik Sahakari Bank Limited, Stadium Shopping Centre, Stadium Ground Jodhpur-19.
2. M/s. Sunil Synchem Limited, 17/18, Old Industrial Area, Alwar, including its five branches at (1) New Delhi (2) Bombay (3) Calcutta (4) Madras (5) Ahmedabad.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(18)/87-SS. II]

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1987

का. भा. 1929 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप-

बन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

1. मसर्स तेजपुर गैस एजेंसी, मेन रोड, तेजपुर
2. मसर्स नार्थ इस्टर्न एंटरप्राइजेज, जेल रोड, गोवाहाटी-1
3. मसर्स इण्डियन रोड लिनर्स, लक्ष्मी चटर्जी लेन, पान बाजार, गोवाहाटी-1
4. मसर्स बरीवाल कंस्ट्रक्शन, जगो रोड, कस्बा नागांव
5. मसर्स द्वारका प्रसाद दिदवानिया, कामरूप चैंबर रोड, फैंसी बाजार, गोवाहाटी-1
6. मसर्स ए. के. कान्डू, डालीगांव, कोकराझार
7. मसर्स एस कुमार एंड ब्रदर्स, प्रधगांव रोड, गोवाहाटी-1

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, को उक्त धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(24)/87-एस. एस-2]

New Delhi, the 16th July, 1987

S.O. 1929.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Tezpur Gas Agency, Main Road, Tezpur.
2. M/s. North Eastern Enterprises, Jail Road, Guwahati-1.
3. M/s. Indian Road Liners Laxmi Chatterjee Lane Panbazar, Guwahati-1.
4. M/s. Beriwal Construction, Jagiroad, District, Nagaon.
5. M/s. Dwarka Prasad Didwania, Kamrup Chamber Road, Fancy Bazar, Guwahati-1.
6. M/s. A. K. Kundu, Dhaligaon, Kokrazhar,
7. M/s. S. Kumar and Brothers, Athgaon Road, Guwahati-1.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(24)/87-SS. II]

का. भा. 1930 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मसर्स सी. पी. डब्ल्यू. डी. डिपार्टमेंटल केन्टीन, विद्युत भवन, नई दिल्ली-1
2. मसर्स दिल्ली सोमिएस बैंकफैर एडवाइजरी बोर्ड, 6 भगवानदास रोड, नई दिल्ली।
3. मसर्स मिडार्थ फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन, 98 मिडार्थ, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19
4. मसर्स राभी एंड कंपनी, 4551 डिप्टीगंज दिल्ली-106 और इसकी (1) जीआई-106(2) सी-144 मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2 नई दिल्ली-84 स्थित फैक्ट्री।

धतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एम-35019(25)/87 - एम. एम-2]

1. S.O. 1930.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. C.P.W.D. Departmental Canteen Vidyut Bhawan, New Delhi-1.
2. M/s. Delhi Social Welfare Advisory Board, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi.
3. M/s. Siddharth Flat Owners Association, 96, Siddharth, Nehru Place, New Delhi-19.
4. M/s. Rance and Company 4551, Deputy Ganj, Delhi-6, including its two factories (i) G.I. 106 and (ii) C. 144, Mayapuri Industrial Area Phase-II, New Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[No. S. 35019(25)/87-SS. II]

का. प्रा. 1931—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1-8-1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

बंगलूर जिले में होसकोटे ताल्लुक के अधीन हुब्ली कसाबा में पंचायत टोड्डहुल्लूर तथा चौक हुब्ली गांव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।

[संख्या एम - 33013/25/87 - एम. एम - 1]

S.O. 1931.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st August, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act, shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely :—

"The Area comprising of the Village Chokkahalli and Doddahullur Panchayat of Hubli Kasaba Under Taluk Hoskote in District Bangalore".

[No. S-38013/25/87-SS I]

का. प्रा. 1932—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

- (1) मैसर्स धमरा केरला इंडस्ट्रीज, टाउन हॉल रोड, अरनाकुलम कोचिन-18, कन्नूर ताल्लुक, अरनाकुलम कस्बा
- (2) मैसर्स श्रीधीभा टाकीज साकेरी गांव, पेरालासरी, केन्नूर ताल्लुक और कस्बा
- (3) मैसर्स सिलिस कविता, 35, एम एम (कविता एंटरप्राइज) केन्नूर
- (4) मैसर्स केरल गैरेज दारासारा रोड, अरनाकुलम

- (5) मैसर्स पीएम भाटो हाउस, पोस्ट आफिस रोड, त्रिवूर-1
- (6) मैसर्स मैन्यूलसन्स जनरल सर्विसेज, एम ओ रोड, त्रिवूर
- (7) मैसर्स मैन्यूलसन्स डाटा प्रोसेसिंग कन्सल्टेन्सी सर्विस, एम ओल्ड रोड, त्रिवूर-1
- (8) मैसर्स पी. टी. मैन्यूल एंड मन्स राउण्ड वीरट, त्रिवूर
- (9) मैसर्स माननाम कालेज आफ फार्मासिटीकल मैडिसिन माननाम नगर, त्रिवूर, त्रिवूर-10
- (10) मैसर्स के. एम. वुग रिसर्च वैट्रोडिज (प्राइवेट) लि., थैस्ट चेल्लाकुट्टी, त्रिवूर कस्बा
- (11) मैसर्स सेन्ट जोन बो वापटिस्ट मो० एस० आई० स्कूल, एलवे-1
- (12) मैसर्स नाथल डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटरप्राइजिज, 39/795, अरनगय काग रोड, अरनाकुलम, कोचीन-18
- (13) मैसर्स त्रिवेणी रबर (प्राइवेट) लि., इंडस्ट्रीयल स्टेट, इट्टुमनुर कोट्टायम (कस्बा)
- (14) मैसर्स अमदावती ट्रस्ट, एम. सी. नं. 17/2368, मेन रोड, कल्लन-1
- (15) मैसर्स महेश्वरी टैक्सटाइल कोलर्स, एम टी नं. 17/2367, मेन रोड, कल्लन-1
- (16) मैसर्स लक्ष्मण दाम एंड कंपनी, एम जी रोड, अरनाकुलम, कोचीन-35
- (17) मैसर्स लक्ष्मणदाम एंड मन्स एम जी रोड, अरनाकुलम, कोचीन-35
- (18) मैसर्स विश्वेश्वरी आई हास्पिटल, दिवाखुण रोड, त्रिवूर-4
- (19) मैसर्स छेरीपारामबिल स्टोर्स, थोड्डुजहा (ग्राम और ताल्लुक) इट्टुक्की कस्बा
- (20) मैसर्स चेतीपारामबिल टैक्सटाइल डोर नं. 7/75 थोड्डुजहा इट्टुक्की कस्बा
- (21) मैसर्स जोकस एंटरप्राइजिज, पदीगुआकरा बिल्डिंगज बाय, एम सी ए रोड, कोट्टायम
- (22) मैसर्स अर्यायाम एम सी नं. 17/924, 925 मेन रोड, कल्लन-1 और इसकी बम्बई-1 स्थित शाखा
- (23) मैसर्स ज्ञान बोस्को कुरिज (प्राइवेट) लि. ज्ञान बोस्को बिल्डिंग 26/643, राइस बाजार त्रिवूर-1 और इसका बंगलूर स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
- (24) मैसर्स वारागनासारी स्कूल आफ म्यूजिक काटन हिल बाजूयाकाड, त्रिवेन्द्रम-14 और शाही त्रिवेन्द्रम-14 मिया बो तावाए
- (25) मैसर्स अरुबीकारा फार्मस सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नं. 603 अरुबीकारा पोस्ट आफिस और इसकी (1) चेरीयाकोनी (2) मैन्यूर डिपोज है चेरीयाकोनी एंड अरुबीकारा (3) प्रोविजन स्टोर है आज़हीकोड अरुबीकारा चेरीयाकोनी (4) टैक्स डिपो है अरुबीकारा स्थित चार शाखाएं।

धतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एम - 35019(28)/87 - एम. एस - 2]

S.O. 1932.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Amara Kerala Industries, Town Hall Road, Ernakulam Cochin-18, Kanayannur Taluk Ernakulam District.

2. M/s. Sreethibha Talkies, Makeri Village, Peralasari Cannanore Taluk and District.
3. M/s. Little Kavitha, 35, MM (Kavitha Enterprises) Cannanore.
4. M/s. Kerala Garage Darumara Road, Ernakulam.
5. M/s. Fashion Auto House, Post Office Road, Trichur.
6. M/s. Manuelsons General Merchants, M.O. Road, Trichur.
7. M/s. Manuelsons Data Processing and Consultancy Services, M.O. Road, Trichur-1.
8. M/s. P.T. Manuel and Sons, Round West, Trichur.
9. M/s. Mannam College of Pharmaceutical Sciences, Mannam Nagar, Vyyur, Trichur-10.
10. M/s. K. S. Durg Research Laboratories (Private) Limited, West Chalakudy, Trichur District.
11. M/s. St. John The Baptist C.S.I. School, Alawye-1.
12. M/s. Novel Distributing Enterprises, 39/795, Arangath Cross Road, Ernakulam Cochin-18.
13. M/s. Triveni Rubber (Private) Limited, Industrial Estate, Ettumanoor, Kottayam (District).
14. M/s. Amaravathy Trust, M.C. No. XVII/2368, Main Road, Quilon-1.
15. M/s. Maheswari Textile Dealers, M.C. No. XVII/2367, Main Road, Quilon-1.
16. M/s. Lachmandas and Company, M.G. Road, Ernakulam, Cochin-35.
17. M/s. Lachmandas and Sons, M.G. Road, Ernakulam Cochin-35.
18. M/s. Vijayasree Eye Hospital, Dilkush Road, Trichur-4.
19. M/s. Chettiparambil Stores, Thodupuzha (Village and Taluk), Idukki District.
20. M/s. Chettiparambil Textiles Door No. VII/75, Thodupuzha Idukki District.
21. M/s. Jofex Enterprises, Padijarekara Buildings, Y.M.C.A. Road, Kottayam.
22. M/s. Ayyappas M.C. No. XVII/924, 925 Main Road, Quilon-1, including its branch at Bombay.
23. M/s. Don Bosco Kuries (Private) Limited, Don Bosco Building XXVI/643, Rice Bazar, Trichur-1, including its registered office at Bangalore.
24. M/s. Tharanganisari School of Music Cotton Hill Vazhuthacaud, Trivandrum-14, including its branches at Trivandrum and Calicut.
25. M/s. Aruvikkara Farmers Service Co-operative Bank Limited, No. 6033, Aruvikkara Post Office, Pin-695564 including its branches at (1) Cheriyakonni (2) Manure Denots at Cheriyakonni and Aruvikkara. (3) Provisions Stores at Azhicoor Aruvikkara and Chmiyakonni (4) Tax Depot at Aruvikkara.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(26)/87-SS-III]

का.प्र. 1933.-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी विविध निधि और प्रकीण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :-

- (1) मैसर्स सुमईयाजी को-ओपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर को-ओपरेटिव सोसाइटी, एम डी 18 सुमई थागल गांव एंड पी. वाया कानेरी पाकम एम ए कस्बा
- (2) मैसर्स लक्ष्मी बिस्वास (टिकिन सेंटर) 137 त्रिची रोड, तामकल-12

- (3) मैसर्स एस. ए. उल्मानाथन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, 91 पी बाजीनाथपर स्ट्रीट, स्वर्णापुरी सेलम-4
- (4) मैसर्स गंगा डायर्स, 3/38 कन्नयलपल्ली मेन रोड, गुगुरा सेलम-6
- (5) मैसर्स सी एसएल यूनिट्स एम्प्लाइज को-ओपरेटिव लिमिटेड एंड क्रेडिट सोसाइटी, बिन्दुवाचालम
- (6) मैसर्स घाटें इंडिया 5/117 मारयानापुरम रोड, शिवकासी
- (7) मैसर्स शंकरेश्वरी फाइन घाटें, 5 ए बी टी पुदूर स्ट्रीट, शिवकासी
- (8) मैसर्स सी एम सी लसा सोसाइटी, लसा पोस्ट आक्रिम-632209 एन ए कस्बा
- (9) मैसर्स जयन्ता टेक्सटाइल, 92 के बी विन्ना प्यानेकन पालायाम कोमरापालायाम 1983
- (10) मैसर्स प्योरलेक कार्बन एंडस्ट्रीज, चेवराटारोड मुथापलपट पांवेचेरी-3
- (11) मैसर्स कोमिल कार लेबर एक्सपोर्ट्स, 53 सैवनहमत रोड परिक्रामेट, मद्रास-3 और इसके (1) कानपुर (2) 27, मिर्जा गालिव स्ट्रीट कलकत्ता-16 (3) बम्बई (4) नई-दिल्ली-1 स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालय
- (12) मैसर्स जयप्रिया "हॉलिंग लिमिटेड प्रशासनिक कार्यालय 23 बलम गार्डन III स्ट्रीट मद्रास-6 और इसका 27, बेलम गार्डन III स्ट्रीट मद्रास-6 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
- (13) मैसर्स ट्रेक एप्लायनसिज (प्राइवेट) लिमिटेड, 192 माऊंट रोड लिटिल माउंट मद्रास-15 और इसका 5 म्मिथ रोड, माउंट रोड मद्रास-2 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
- (14) मैसर्स बालकन इलेक्ट्रॉनिक्स II-34, इलेक्ट्रॉनिक कैम्पस मद्रास-41 और इसका 14, 1 एवेन्गु, मद्रास 20 स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय।
- (15) मैसर्स श्री अन्नगरामाजी मैथ इन्डस्ट्रीज यामानएवेकनरत्ती (बायासलूर) एम्.न. 127/6 कामराज कस्बा और इसका 44 अमान कोएनपली स्ट्रीट, शिवकासी स्थित कार्यालय।
- (16) मैसर्स तमिलनाडु प्राइवेट टेली बैंक, 24 मैरुवोनाथन रोड, त्रिची-1 और इसका 344 किंग बाजार त्रिची-3 स्थित प्रशासनिक कार्यालय।
- (17) मैसर्स अस्मा इन्डस्ट्रीज नं. 15 निहिरननार रोड, चोरमेट, मद्रास-44 और इसका नं. 5 रावशानीरा एवेन्गु, बाम गार्डन मद्रास-88 स्थित प्रशासनिक कार्यालय।
- (18) मैसर्स सरया केसुधो कैमिकल्स, सी-12 सी इन्डस्ट्रीयुन टाउन, मारियमलाए नगर, मद्रास-209 और इसका 16 आठवी गली, लक्ष्मी नगर, नंगालूर, मद्रास-61 स्थित प्रशासनिक कार्यालय।
- (19) मैसर्स केप्लानीप्रपात एण्ड कम्पनी टैक्सटाइल मैयूफरचरर्स पोस्ट बाक्स नं. 118 कोमरापालायाम 183 और इसकी बापामारा नं. 28 पेराताथरकाडु बिन्नायनरत्तायार, कोपारापोलायाम-183 स्थित फैक्ट्री।
- (20) मैसर्स थरमिण्ड प्रोससर, पंचायन रोड, पेक्कुतुडो, मद्रास-96 और इसकी प्लाट नं. 18 ड. नं. 13 श्रीराम नगर, तिरुवानमपुर मद्रास-41 स्थित शाखा।
- (21) मैसर्स श्रीराम एण्ड कम्पनी, 41 गुडी इण्डस्ट्रीयुन स्टेट, इक्काडुबामल मद्रास-97 और इसकी बी-34(71) चार अशोक नगर मद्रास-83 स्थित शाखा।
- (22) मैसर्स डा रामनंद मुकुर्डी कस्बा पावनेरु शाहरी को-ओपरेटिव मार्केटिंग फैब्रिकेशन, लिमिटेड करा. 754, 149 कामराजार मलास मगुरई-9 और इसकी मद्रास तथा मगुरई स्थित 9 शाखाएं और 6 स्टाल्स।



- (23) मैसर्स टी 1401 ओरथानद को-ओपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड पूरुत ओरथानद और इसकी (1) पापानद ओरथानद टी के (2) कुनामानगलाम ओरथानद टी के (3) कम्पानद कोलिर ओरथानद टी के. (4) ओरथानद डिपो ओरथानद स्थित चार शाखाएं।
- (24) मैसर्स मुधु इन्जीनियर्स बक्स, 4 ए/25 कोडाए बिल्डिंग ओ सी रोड डाइवार्ड कुटई सेलम-1 और इसको मधु सर्विज स्टेशन गुणए हनुपालायम रोड सेलम-15 स्थित शाखा।
- (25) मैसर्स त्रिची पी आर कारुकीयान नादार एण्ड कम्पनी 344 विंग बाजार स्ट्रीट त्रिची-8 और इसकी (1) न. 1 लूस-कार स्ट्रीट त्रिची 8 (2) न. 15 रवास कारा स्ट्रीट त्रिची-8 स्थित दो शाखाएं।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[संख्या एस-35019(20)/87-एस.एस. 2]  
ए.के. भट्टराई, प्रवर सचिव

S.O. 1933.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely,

1. M/s. Sumaithangi Co-operative Milk Producers Society M.D. 18, Sumaithangi Village and Post (Via) Kaveripakkam N.A. District.
2. M/s. Lakshmi Vilas (Tiffin Centre) 137, Trichy Road, Namakkal-12.
3. M/s. S.A. Ulaganathan Engineering Contractor, 90-C, Vanjinathadyer Street, Swarnapuri, Salem-4.
4. M/s. Ganga Dyres, 3/38, Karungalpatty Main Road, Gugai-Salem-6.
5. M/s. The Tecal Units Employees Co-operative Thrift and credit Society Virudhachalam.
6. M/s. Art India, 5/177, A. Marayana Puram Road, Sivakasi.
7. M/s. Sankareswari Fine Arts, 5, A.V.T. Pudur Street, Sivakasi.
8. M/s. CMC—Rusha Society, Rusha, Post Office-632209, N.A. District.
9. M/s. Chandra Textiles, 92-K, 3 Chinnappanaichkanpalayam, Komarapalayam-183.
10. M/s. Purelec Carbon Industries, Chevrapet Road, Muthialpet, Pondicherry-3.
11. M/s. Council of Leather Export, 53, Sydenhams Road, Periamet, Madras-3, including its Regional Offices at (1) Kanpur (2) Calcutta-16 (3) Bombay and New Delhi.

12. M/s. Jaipriya Holdings (Private) Limited, 24 Wallace Garden III Street, Madras-6, including its Registered Office at 27, Wallace Garden III Street Madras-6.
13. M/s. Trak Appliances (Private) Limited, 192, Mount Road, Little Mount, Madras-15, including its registered Office at 5, Smith Road, Mount Road, Madras-2.
14. M/s. Balcon Electronics, II-34, Instronic Campus, Madras-41, including its Registered Office at 14, I Avenue, Madras-20.
15. M/s. Sri Alagarsamy Match Industries, Thammanai-cken Patti (Via Sattur) S. No. 127/6, Kumaraj District, including its office at 44, Ammankoilpatti Street, Sivakasi.
16. M/s. Tamil Nadu Auto Stores Prtrol Bank, 24, Macdonalds Road, Trichy-1, including its Admn. office at 344, Big Bazar, Trichy-8.
17. M/s. Alsa Industries, No. 15, Thiruneceramalai Road, Chrompet, Madras-44, including its Admn. Office at No. 5, Raghava Veera Avenue, Boes Garden Madras-86.
18. M/s. Satya Cashev Chemicals, C-12-C Industrial Town, Maraimalai Nagar, Madras-209, including its Adm. Office at 16, 8th Street, Lakshmi Nagar, Nanganallur, Madras-61.
19. M/s. K. Palaniappan and Company Textile Manufacturers B.B. No. 118 Komarapalayam-183, including its Factory at Bymash No. 28, Peranatharkadu, Chinnappanaicken-aalayan, Komarapalayam-183.
20. M/s. Therminid Processors, Panchayat Road, Perungudi, Madras-96, including its branch at Plot No. 18, D. No. 13, Sri Ram Nagar, Thiruvannamiyur, Madras-41.
21. M/s. Sri Ram and Company, 41, Guindy Industrial Estate, Ekkaduthangal, Madras-97, including its Branch at B-34 (71) IV, Ashok Nagar, Madras-83.
22. M/s. The Ramand Madurai District Palmyrah Jagery Co-operative Marketing Federation Limited, Q-754, 149, Kamarajar Salai, Madras-9, including its Nine Branches and six stalls at Madras and Madurai (Tamil Nadu).
23. M/s. T. 1401 Orathanad Co-operative Marketing Society Limited, Pudur Orathanad, including its branches at (1) Papanad Orathanad T.K. (2) Kulaman-galam Orathanad T.K. (3) Kasanadu Koilur Orathanad T.K. (4) Orathanad Depot, Orathanad.
24. M/s. Madhu Engineering Works, 4-A/25, Kothai Building, D.D. Road, Dadubaikuttai Salem-1 including its branch Madhu Service Station Gurai-Eruma-palayam Road, Salem-15.
25. M/s. Trichy P. R. Karuppan Nadar and Company, 344, Big Bazar Street, Trichy-8, including its two branches at (1) No. 1 Luscar Street Trichy-8 (2) No. 15, Glasskara Street, Trichy-8.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(20)/87-SS. II]  
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1987.

का० आ० 1934 :—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप धारा (1) के उपबन्ध, जहाँ तक इसमें विहित प्ररूप में, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के प्ररूप IV, V और IX में अतिरिक्तिक कार्य का रजिस्टर, मस्टर रोल, और मजदूरी का रजिस्टर रखना अपेक्षित है, सम्बन्धी पक्षों के संपत्ति, विधि, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, मुख्य इन्जीनियर, चिन्ता और श्रम विभागों के उन कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी दत्त निर्धारित की गई है, बशर्ते कि ऐसे कर्मचारियों के विवरण प्ररूप छ 14 ख/1 में, जिसे इस अधिसूचना की अनुसूची में संलग्न किया गया है और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) और न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के प्रयोजनार्थ अतिरिक्तिक कार्य का रजिस्टर, मस्टर रोल, मजदूरी का रजिस्टर माने जाएंगे में रखे जाएंगे और शर्तें यह भी कि विभिन्न तारीखों को किसी कर्मकार द्वारा किए गए अतिरिक्तिक कार्य के खदों की संख्या और किसी माह में कर्मकारों द्वारा 615 GI/87-5

किए गए अतिरिक्तिक कार्य के घंटों के योग को प्रस्तावित प्रथम के क्रमशः कालम 10 और कालम 16 के नीचे उस पंक्ति, जिसमें कर्मकार का नाम लिखा है, के सुरुवात बाद वाली पंक्ति में उल्लेख किया जाएगा।

[सं. एस-32014/2/87-डब्ल्यू.सी. (एम.डब्ल्यू.)]  
अधिवक्ता सूचका, उपसचिव

## अनुसूची

माह.....के लिए मस्टर रोल

छ 14/ख/1

अविष्य निधि लेखा संख्या	क्रम संख्या	आकस्मिक अवकाश	वैकल्पिक अवकाश	पदनाम प्रथम बार नियुक्ति की तारीख	धर्म न्यूनतम मजदूरी की दर मूल नईगाई- भत्ता वेतनमान	कर्मचारी का नाम नया पिता/पति का नाम	टिकट संख्या	विभाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

10

न्यूनतम मजदूरी दर	अधिकालिक दर	प्रति सप्ताह के सामान्य कार्य घण्टे	उन दिनों/घंटों का संख्या जिनके लिए अधिकालिक प्राप्ति है	कुल उपस्थिति/ किये गए कार्य की मात्रा	वेतन दर	वेतन	
र. व.	र. व.		एम. डब्ल्यू. ए	पी.टी.धार.		र. व.	
11	12	13	14	15	16	17	18

## वास्तव में भत्ता की गई मजदूरी की दरें

भत्ता	अन्य भत्ते विशेष वेतन मात्रा	परिपूरक (नगर) भत्ता	नईगाई भत्ता	भकान किराया भत्ता	अतिरिक्तिक एम. डब्ल्यू. ए.	पी.टी.धार.	राशि भार
र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.
19	20	21	22	23	24	25	26

## कटौतियां

कुल देय मजदूरी	अविष्य निधि अंशदान अविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी	अविष्य निधि अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी	बी.पी.एफ. अंशदान	अविष्य निधि अग्रिम	आई.पी.ओ. एस.आई.पी.	आयकर	सहाकारी ऋण समिति
र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.	र. व.
27	28	29	30	31	32	33	34

कटौतियां													
वेतन वचन योजना		ग्राहक का किराया		बिजली खर्च		अन्य कटौतियां रथोद्धार आदि भ्रमिन		वेतन से वचन करने की योजना		कांड़ा मजदूर रिनोल्ड्स इस्टीमेट		कुल कटौतियां	
र.	पै.	र.	पै.	र.	पै.	र.	पै.	र.	पै.	र.	पै.	र.	पै.
35		36		37		38		39		40		41	

वास्तव में वेतन मजदूरी		प्रतिकालिक भत्ता की अभावगी करने की तिथि		टिप्पणी	
42		43		44	

New Delhi, the 15th July, 1987

S.O. 1934.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby directs that for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the provisions of sub-section (1) of section 18 of the said Act, in so far as it requires a Register of Overtime, Muster Roll and Register of Wages to be maintained in the prescribed forms, namely Forms IV, V and X of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 shall not apply in relation to the employees of the Estate, the Legal, the Chief Mechanical Engineer's, the Chief Engineer's, the Medical and the Labour Departments of Bombay Port Trust, for whom minimum rates of wages have

been fixed under the said Act, subject to the condition that particulars of such employees shall be maintained in Form G 14B/1 which is set out in the schedule to this notification and which shall be deemed to be the Register of Overtime, Muster Roll and Register of Wages for the purpose of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 and subject also to the condition that the number of hours of overtime put in by a worker on different dates as well as the total of overtime work put in by the workers in a month shall be indicated in the proposed form under columns 10 and 16 respectively in the line immediately following the line on which the name of the worker is entered.

[No. S-32014/2/87-WC(MW)]  
ASHWINI LUTHRA, Dy. Secy.

## SCHEDULE

Muster Roll for the month of ..... G 14 B 1

P. F. Account No.	Sl. No.	Casual Leave	Optional Holidays	Designation/ Date of first appointment	Rate of Minimum Wages Payable Basic + D.A. Scale of pay	Name of the employee with Fathers/Husbands Name	Ticket No.	Sex
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31								

10

Minimum Wage Rate		Overtime Rate		Normal Hrs. per week		No. of days/Hrs. for which overtime is admissible		Total attendance/ Unit of work done		Rate of pay		Pay	
Rs.	P.	Rs.	P.			M.W.A.	P.T.R.					Rs.	P.
11		12		13		14	15	16		17		18	

## RATE OF WAGES ACTUALLY PAID

Allowance		Other Allowances Sp. Pay Etc.		Compensatory (City) Allowance		Dearness Allowance		House Rent Allowance		Over-time M.W.A.		Night Weightage	
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
19		20		21		22		23		24		25	26

## DEDUCTIONS

Gross Wages payable	P.F. Contr. Employees Governed by Cont. P.F. Scheme	P.F. Contr. Employees Governed by Pension Scheme	V.P.F. Subscription	P.F. Advance	I.P. & S.I.P.	Income Tax	Co-op. Credit Society
Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
27	28	29	30	31	32	33	34

## DEDUCTIONS

Salary Savings Scheme	Rent for quarters	Electric Energy	Other Deductions Festival Adv. Etc.	Pay Roll Saving Scheme	Sports Club Reynold's Inst.	Total Deductions
Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
35	36	37	38	39	40	41

Actual Wages payable	Date of O.T. Payment	REMARKS
42	43	44

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1987

का.प्र. 1935 :—प्रयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, फतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधन से सम्बद्ध निवृत्तों और उनके कर्मचारियों के बीच, अतुल्य में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, न. 2, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 39 जून, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 16th July, 1987

S.O. 1935.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Futwah Islampur Light Railway Company Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th June, 1987.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 161 of 1986

In the matter of industrial dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Futwah Islampur Light Railway Co. Ltd., Mercantile Building, 9 Lal Bazar Street, Calcutta-700001 and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the E. Railway : Shri B. N. Prasad, Authorised Representative.

On behalf of the workmen : The concerned workman himself.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Railway

Dated, Dhanbad, the 22nd June, 1987

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 had referred the following dispute to the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, vide Ministry's Order No. L-41012(29)/85-D.II (B) dated, the 24th June, 1985. But subsequently the Government of India, Ministry of Labour through their Order No. L-41012(29)/85-D.II(B) dated the 8th April, 1986 has transferred the same to this Tribunal for adjudication.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Futwah Islampur Light Railway Co., Calcutta in dismissing the services of their workman Shri K. N. Prasad, Ex-Assistant Traffic Inspector w.e.f. 13-7-84 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

Futwah Islampur Light Railway Company Limited (hereinafter referred to as FILR for brevity) was acquired by the Union of India with effect from 1-1-86 and from that day it has ceased to carry any business. Its connected staff, record and assets have also been taken over by the Union of India which has also closed down the operation of FILR completely and presently the company has a skeleton staff consisting of the G.M., Chief Engineer, Industrial Relations Officer and three clerks all of whom are superannuated and as such were not taken over by the Union of India represented by its Eastern Railway. The company is existing only with a view to going into liquidation. The concerned person Shri Kashinath Prasad was employed as Asstt. Traffic Inspector in FILR in managerial/administrative capacity and was not a workman. There was no relationship of employer and employee between the company and the concerned person while the concerned person was working as Asstt. Traffic Inspector in FILR. He was chargesheeted vide Ext. M-1 dt. 23-8-83. He was charged for his action and lapses consti-

tuting gross indiscipline in subordination, high handedness and the defiance of orders of superiors which tantamounts to serious misconduct on his part. He was charged on 8 counts which are as follows :—

1. That on 30-7-83, AEN/HIL had sent Shri Surendra Prasad Peon of Dy. Ts Office to your house at about 10.10 hours to collect keys of the new office on the ground floor (previously used as upper class waiting room) but you refused to hand over keys to him which he reported back to AEN.
- (a) that afterwards when you came to the Station, AEN/HIL personally requested you to give him keys of the office and that of the attached latrine but you again and again refused to do so and started loose talks with AEN on the platform creating an ugly scene. This continued to do even in presence of Dy. TS who by then had reached at the spot on the platform.
- (b) That even when the Dy. TS asked to give the key of latrine but you did not comply and instead you used very vulgar language to AEN in presence of Dy. TS and others.
- (c) That all the artisans staff of AEN who were called to do certain repair works on the ground floor office and latrine remained idle wasting thus a day of company's labour due to your unwarranted obstinacy.
2. That on 6th June, 1983 in course of Joint Enquiry into Shri Chok Narain TTE's case you in complete disregard to discipline and decorum flared up against the Enquiring Officers and indulged in altercation and uttered sentences raising provincial and communal feelings.
3. That on 6th August, 1983, you used insulting and abusive language against the Medical Officer of the Railway in presence of other staff on the open platform.
4. That on 30th July, 1983, you misbehaved with APO at CRH in presence of AAO and the Traffic Superintendent, when APO had last visited Futwah.
5. That on 17th August, 1983 you were to follow the checking programme by 2 Dn. and while doing so you indulged in instigating passengers against the A.N. and in an attempt to slur the name and image of the AEN, you made false allegation and cooked story to the extent that AEN wanted to get you killed.
6. That on 19th August, 1983 on reaching with the Squad at Islampur by 5 UP train in the evening, you indulged in loudly abusing the Senior Officers in general and the AEN/HIL in particular within his AEN hearing distance that the AEN, TS and all other top officer are thieves and they when come here they take Murga to improve their health only.
7. That on 1st August, 1983 you were specifically instructed by Dy. TS Futwah about the Magisterial Checking on 2nd August, 1983 and to accompany the Checking party. You avoided and did not accompany the party on plea of being ill, but soon after the party had returned, you went on line by 3 UP mixed train of 2nd August, 1983 with the Officer-on-Special duty. You thus disregarded the instruction of the Superior authority.
8. That Dy. TS/Futwah intimated you on 2nd August, 1983 about Checking Programme chalked out vide TS's letter No. SE/FI/Checking dated 2nd August, 1983 and advised you to submit report on each day checking but you paid no heed and did not submit any report, nor carried out any checks as per the programme fully.

The said charge sheet was served on the concerned person and he was called upon to furnish his explanation. The concerned person by letter dated 31st August, 1983 submitted his reply to the said chargesheet denying all the charges. His explanation is Ext. M-2 in the case. The management of FILR found his explanation to be unsatisfactory and there- 615 G of 1187—6.

after constituted a committee of enquiry to enquire into the charges against the concerned person. The enquiry Committee was constituted by the General Manager on 16th February, 1984 and the said committee commenced its sitting on 22nd March, 1984. On the first sitting of the enquiry the concerned person objected to one of the members Shri P. K. Das acting as a member of the committee on the ground of business. In view of the said objection Shri R. K. Das resigned from the Enquiry Committee. The General Manager reconstituted the enquiry committee consisting of 2 persons and the said reconstituted enquiry committee recommended its sitting on 2nd May, 1984. The case of the management is that on that day after some preliminary discussion about the procedure, the concerned person started behaving in arrogant, insolvent and violent manner and shouted at the Chairman of the Enquiry Committee and the management representative. On being asked by the Chairman to stop shouting and confine himself in the enquiry proceeding the concerned person read out and filed a letter dated 2nd May, 1984 and then walked out of the enquiry committee stating that he is not taking any further part in the enquiry proceeding as the Chairman of the enquiry committee was biased and against him as such the enquiry committee proceeded ex parte against the concerned person. All the management's witnesses were examined in the absence of the concerned person. The enquiry Committee held that all the charges contained in the chargesheet against the concerned person except charge No. 5 were established against him. The General Manager accepted the finding of the enquiry committee and by his order dated 12th March, 1984 passed an order of dismissal of the concerned person from his service. By his letter dated 13th July, 1984 the concerned person was informed about the finding of the enquiry committee and his dismissal from services. It is the further case of the management that the concerned persons had been given chance to defend his case but himself chose not to participate in the enquiry proceeding. The finding of the enquiry committee were passed on the evidence produced before it. There is no question for the management to concede the demand of the concerned person to reinstate him in service. The concerned person raised an individual dispute before the ALC(C) which ended in failure.

FILR appeared and filed their W.S. before this Tribunal. The Divisional Railway Manager, Danapur who is in the control of FILR after nationalisation also appeared and filed their W.S. adopting the W.S. earlier filed by M/s. FILR.

The case of the concerned person is that he joined M/s. FILR company of M/s. Martin's Light Railway Calcutta with effect from January, 1969 and continued to serve in various capacities. He was recruited as probationer T.C. at Arrah in Arrah Sasaram Light Railway company of M/s. Martin Railway with effect from 2nd December, 1953. He was confirmed as T.C. on 1st August, 1954. He was promoted in various capacities and his services were utilised in different places of Martin Railway Company. Lastly he was posted at Futwah in FILR as Travelling Ticket Examiner in January, 1969. He was promoted to the post of Asstt. Traffic Inspector on 16th June, 1980 and was confirmed on the said post on 1st August, 1981. He was also entrusted with the work of Vigilance Inspector from 1st May, 1983 and he shouldered the double charge of Asstt. Traffic Inspector and Vigilance Inspector. The concerned person had to submit confidential report about the performance of Officers/staff of FILR in the capacity of Vigilance Inspector as per the instruction of the General Manager. He was at liberty to report to the General Manager in regard to the confidential and important matters, to investigate/verify the different aspect of working of traffic department, boost up revenue generation, plug all possible avenue of pilferage, misappropriation and realisation of the railway revenue. Due to the said activities of the concerned person some of the officers like Traffic Superintendent, Chief Engineer, Asstt. Engineer, Assistant Personnel Officer and Medical Officer had developed grudge against him and he was their eye sore. The dismissal of the concerned person from service with effect from 13th July, 1984 was an outcome and malice and grudge against him. The concerned person had made appeal to the management of M/s. FILR against the order of dismissal but the management did not respond to his appeal. Lastly the concerned person made a demand before the management on 13th July, 1984 and when the management did not concede to his demand, the concerned person raised an industrial dispute before the

ALC(C) Patna on 10th August, 1984. The ALC(C) held conciliation proceeding which ultimately failed and thereafter the present reference was made. The Traffic Superintendent vide his order dated 22nd August, 1983 withdrew the dual charge of vigilance inspector entrusted to the concerned person by the General Manager without any authority. The Traffic Superintendent had issued chargesheet dated 23rd August, 1983 mentioning the proposed punishment for removal from service without calling for any explanation from him. The charges levelled against the concerned person was maliciously false as there is no room for the management to do so. The concerned person replied to the charges levelled against him vide his letter dated 31st August, 1984. There was considerable delay in holding the enquiry against the concerned person so that he may be put to untold hardship. The domestic enquiry held against the concerned person was against the normal procedure. The concerned person was not given a second and final show cause notice before imposition of the penalty of dismissal. The action of the management in dismissing the concerned person is malicious and malafide and as such he is entitled to be reinstated with full back wages.

The management had earlier prayed that as the concerned person has been dismissed from service after holding domestic enquiry into the charges served upon him, it first be decided as a preliminary issue whether the domestic enquiry against the concerned person was fair proper and in accordance with the principles of natural justice. Both the parties adduced oral and documentary evidence on the preliminary point and thereafter by the order dated 2nd March, 1987 the Tribunal held that the enquiry was fair proper and in accordance with the principles of natural justice and that the enquiry committee was not biased against the concerned person. Thereafter the case was set for hearing on merit on the materials which were already on record of the enquiry proceeding.

Now the point for consideration is whether the dismissal of the concerned person was justified. In this connection we have to find whether the charges levelled against the concerned person were established in the domestic enquiry. It is also to be seen whether the punishment of dismissal is harsh.

The management examined 15 witnesses before the enquiry committee. Admittedly the concerned person had appeared in the enquiry proceeding but himself left the proceeding stating that he would not participate in the enquiry proceeding. The enquiry committee therefore proceeded *ex parte* against the concerned person.

Now let us examine the evidence adduced on behalf of the management and we will be discussing evidence separately on each charge.

The allegation in charge No. 1 against the concerned person has been stated in the earlier paragraphs of this Award. Shri N. C. Banerjee, AEN Hilasa wrote a letter to the Traffic Superintendent, Futwah which has been marked Ext. 3 by the Enquiry Officer and form part of the enquiry proceeding. This Ext. 3 was the origin on the basis of which charge No. 1 was framed against the concerned person. It is stated by Shri Banerjee in Ext. 3 that he had arranged for some men to carry out repair work in upper class waiting room on 30th July, 1983 and that as the room was locked he sent Surendra Prasad Peon of ATI office to the residence of the concerned person to collect the key but the concerned person refused to give the key of the room, to Surendra Peon. Subsequently the concerned person came to the station and thereafter Shri Banerjee requested him to handover the key of the room. On his several request the concerned person handed over the key of the room of upper class but refused to give the key of the latrine attached to the said room. Shri Banerjee reported the matter to the Dy. Traffic Superintendent who was present there who also asked the concerned person to give the key but the concerned person refused to give the key to Shri Banerjee. It is further stated that the concerned person had hot altercation with Shri Banerjee in presence of the Dy. T. S. and used vulgar language. As the key was not handed over to Shri Banerjee all the artisans whom he had called could not carry out the repair work for which they had been called. Admittedly Shri Banerjee could not be produced for his evidence before the enquiry committee as he was murdered on 26th September, 1983. The Peon Surendra was examined before the enquiry committee as witness No. 2. He has stated that he had read Ext. 3 bearing the signature of late Shri N. C. Banerjee. He has stated

that Shri N. C. Banerjee had sent him to the house of the concerned person to fetch the key of the upper class waiting room but the concerned person refused to hand over the key and thereafter he returned and reported the matter to Shri Banerjee. Witness No. 1 is Shri Sukumar Mukherjee, Station Master, Futwah. He has identified the signature of late N. C. Banerjee on Ext. 3. He has stated after reading Ext. 3 that the facts mentioned in it are correct and it is to his knowledge. He has stated that he was present on the date of the incident i.e. on 30th July, 1983 as he was performing his duties in the Station Room and platform. He has stated that late Shri Banerjee wanted the key of the upper class waiting room which was being converted into office. He has stated that late Shri Banerjee told the concerned person that he has brought his men to do some work in the upper class waiting room and as such he asked for the key from the concerned person but the concerned person refused to handover the key to him. He has stated that the concerned person shouted in passion as to who Shri Banerjee was to demand the key and that even if the General Manager attempted to go inside the room he would lock him in the room. Shri Mukherjee further stated that there was hot discussion in which the concerned person also abused Shri Chaturvedi. He has also stated that Shri Banerjee then told the Dy. T.S. who was in the station that the concerned person was not handing over the key and the Dy. T.S. asked for the key from the concerned person who refused to hand over the key. He has stated that the concerned person then shouted that he would pack up the G.M. Traffic Superintendent inside the privy and will beat them and would see who saves them. He further stated that the concerned person abused everybody saying that everybody was thief.

MW-3 is Shri B. C. Ghosh, Dy. T.S., He has stated that he was aware of the incident which took place on 30th July, 1983 regarding the conversion of upper class waiting room into office. He has stated that the facts stated in Ext. 3 bearing the signature of N. C. Banerjee are correct to his knowledge. He has stated that on 30th July, 1983 late Shri N. C. Banerjee approached him and told him that the concerned person was refusing to hand over the key of the upper class waiting room for completion of repair work for which he has brought his men and then this witness asked the concerned person to hand over the keys on which the concerned person flared up and started shouting at Shri Banerjee in his presence using abusive language. He has further stated that the concerned person shouted saying that he would not handover the key even if the orders came from the higher ups. He has stated that Shri Banerjee told the concerned person not to shout at him as he was reporting the matter to the Dy. T.S. whereupon the concerned person retorted in hot words and started using abusive language against Shri Banerjee and the Traffic Superintendent saying that they were thieves, they were trying to harm him and that he would assault them in the latrine. He has stated that the conduct and the action of the concerned person on 30th July, 1983 were highly derogatory, highly indiscipline causing intervention in the company's work and disregard of Sr. Officers orders. MW-5 Ramdeo Mason, MW-7 Chandoo Trolleyman have corroborated the statement of MW-1, MW-2 and MW-3. They have also stated that the concerned person had refused to hand over the key when asked by late Shri N. C. Banerjee and had shouted and abused and threatened to assault. MW-5 and MW-6 Bengali Carpenter have also stated that they could not perform the allotted work as the key were not handed over to late Shri Banerjee. MW-10 Keso Trolleyman and MW-12 Mahendra Khalasi have also stated that the concerned person refused to hand over the key and abused late Shri Banerjee and had threatened to assault and had exchanged hot words with him.

The concerned person had pointed that in the report of Shri Banerjee Ext. 3 the date of occurrence is 29th July, 1983 but in the chargesheet the date of occurrence is 30th July, 1983 and as such there is a vital contradiction regarding the date of the alleged occurrence. On perusal of Ext. 3 it appears that the occurrence took place on 30th July, 1983 and not on 29th July, 1983. Shri Banerjee has only stated in Ext. 3 that he had gone on leave and returned on 29th July, 1983 but he has never stated that the occurrence took place on 30th July, 1983. Thus this objection has no foundation.

It has been submitted by the concerned person that some of the witnesses have stated that the concerned person was talking to Shri Banerjee in English and some witnesses say

that he was talking in Hindi and as such the witnesses should be disbelieved. It will appear from the evidence that the concerned person was speaking both in English and Hindi at the time of occurrence as we have discussed above and there was a large number of witnesses present at the alleged time and some of them heard the concerned person speaking in Hindi while some others heard speaking in English and as such the witnesses stated truthfully regarding the facts which they had heard. The management's witnesses cannot be disbelieved on that account.

Considering the entire evidence it appears that on 30th July, 1983 AEN/HIL had sent Surendra Peon to the house of the concerned person at about 10.00 A.M. to collect the keys of the upper class waiting room and that the concerned person refused to handover the key to the Peon who reported the matter to AEN Shri Banerjee. It will also appear that when the concerned person came to the station on that day Shri Banerjee personally requested him to give the keys of the upper class waiting room and the attached latrine which was refused by the concerned person and he started loose talks with Shri Banerjee on the platform creating an ugly scene which he continued to do even in presence of Dy. T.S. who had arrived there. It has also been established that even when the Dy. T.S. asked the concerned person to give the key of latrine the concerned person refused and used vulgar language to Shri Banerjee in presence of the Dy. T.S. and others. It is also established that the Masons and other staff of AEN who were called for repairing work on the ground floor of the room and its attached latrine remained idle as the concerned person refused to handover the key. Accordingly I hold that the charge No. 1 has been established against the concerned person.

The second charge against the concerned person is that on 6-6-83 in course of joint enquiry into Shri Chok Narain TT's case he in complete disregard to the discipline and decorum flared up against the enquiry officers and indulged in altercation and uttered sentences raising provincial and communal feelings. MW-3 Shri B. C. Ghosh Dy. Traffic Superintendent was the Chairman of the Enquiry committee in the matter of the charges against Shri Chok Narain TTE. He has stated that late Banerjee APN was also a member of the said enquiry committee and they jointly formed the enquiry committee. He has stated that on 6-6-83 he along with Shri Banerjee, were conducting the enquiry into the charges against Shri Chok Narain in which the concerned person Kashinath Prasad was the presenting officer on behalf of the management. He has stated that the concerned person asked a question to Shri Chok Narain which he answered and as the answer was not to the concerned person's satisfaction, he directed the typist who was recording the deposition not to record the said question and answer. MW-3 has stated that late Shri Banerjee opined that since the question has been asked and the answer already been given the same should go on record whereupon the concerned person stood up and flared up using hot and abusive language against Shri Banerjee. He has stated that the concerned person shouted that Shri Banerjee's knowledge was not better than him and that the concerned person knew out Shri Banerjee have become AEN. MW-3 has stated that Shri Banerjee said to the concerned person that this was an enquiry committee and the concerned person should not behave indecently and thereafter the concerned person shouted at Shri Banerjee "Tum Bangali ho karke Behari ko marenga". Thereafter the concerned person walked out from the enquiry committee. MW-3 had submitted his enquiry report in which he had made special observation regarding the said incident. MW-3 has stated that Ext. 4 which is the enquiry proceeding and the finding in respect of Choke Narain. On perusal of Ext. 4 it will appear that a note at the end of Choke Narain's evidence has been written being signed by MW-3 and the other enquiry committee member Shri Banerjee. It is stated in the said note that the ATL (concerned person) flared up and started shouting at AEN saying that Bengali wants to beat Behari. There is no reason to disbelieve MW-3 on the facts stated by him. It appears from the evidence of MW-3 was a man of short temper and had flared up on the members of the enquiry committee which certainly was superior as the enquiry committee before whom the concerned person was working is a management's representative. The use of allowed language is not only unparlia-

mentary but it discloses how indisciplined the concerned person was. The concerned person had misbehaved with the enquiry officer and the members of the enquiry committee had noted down the adverse remark of his behaviour in the proceeding. A criticism has been made on behalf of the concerned person that the typist who was taking down the deposition of the witnesses has not been examined. In my opinion the non-examination of the typist is not of much importance. MW-3 was much more responsible officer that the typist in whose evidence there is no contradiction. I have no reason to disbelieve the evidence of MW-3 which is supported by the notes in Ext. 4 corroborating what he has stated before the enquiry committee. In view of the evidence discussed above I hold that the charge No. 2 has been established against the concerned person.

The third charge against the concerned person is that on 6-8-83 the concerned person used insulting and abusive language against the medical officer of the railway in presence of other staff on the open platform. In this connection there is evidence of MW-8 Shri Rammandan, Pd., TTE, MW-9 Dr. P. K. Choudhury, Medical Officer and two documents Ext. 9 and Ext. 11. MW-8 Shri Rammandan Pd. TTE has stated that the concerned person had been indulging in derogatory talks against the Medical Officer Dr. Choudhury and had talked to him personally to that effect. He has further stated that on 6-8-83 when he was sitting at the platform of Futwah the concerned person came near him and told him that he was the Chairman of the Action Committee but what action he has taken when Janki was reverted from Chowkidar to porter on medical ground when M. O. himself is a T.B. patient. MW-8 has stated that he submitted a letter Ext. 10 dated 9-8-83 to the Medical Officer reporting about the said incident. Ext. 10 is the letter written by MW-8 to the medical officer (MW-9) in which he has stated about the incident which he deposed before the enquiry committee. MW-9 Dr. P. K. Choudhury, M.O. has stated that he submitted a report Ext. 11 dated 9-8-83 to the G.M. about the misbehaviour of the concerned person against him. He has further stated that on some occasion in the past the concerned person used derogatory and abusive language against him and other officers of the FILR. He goes on further to say that he is reporting this incident because the concerned person instigated the Chairman of the Action Committee against him as Janki was reverted on the basis of the medical report submitted by him. Thus he evidence of MW-8 and MW-9 coupled with the documents Ext. 9 and 10 show that the concerned person used insulting language against the M.O. on 6-8-83 on the open railway platform.

The fourth charge against the concerned person is that on 30-7-83 he misbehaved with the Assistant Personnel Officer (hereinafter referred to as APO in short) at Futwah officers rest house in presence of A.A.O. and the T.S. when the APO had last visited Futwah. In this connection MW-14 Shri N. K. Majumdar APO, MW-15 Shri S. K. Ghosh, AAO have been examined and the report of MW-14 Shri N. K. Majumdar Ext. 13 have been filed. MW-14 Shri N. K. Majumdar, APO FILR has stated that the concerned person misbehaved with him at officers rest house, Futwah on 30-7-83 at about 1.6 P.M. in the presence of Shri S. K. Ghosh, AAO and N. N. Chaturvedi. He has stated that he had submitted a report in this connection to the G.M. with a copy to the T.S. on 4-8-83. The said letter is Ext. 13 dated 4-8-83 addressed by MW-14 N. K. Majumdar to the G.M. FILR, Calcutta. MW-14 has stated that while he was discussing the stores matters with Shri S. K. Ghosh, AAO and the Traffic Supdt. at officers rest house Futwah on 30-7-83 the concerned person came to him and shouted at him saying that while the G.M. and the Chief Engineer promised him that he would be given an allowance of Rs. 40, he was sanctioned only Rs. 38 because of MW-14. MW-14 told the concerned person to refer the matter to the G.M. as he was not aware of the matter whereupon the concerned person flared up and shouted at him that while granting the increment to the concerned person his allowance was reduced correspondingly at the instance of MW-14. The witness further stated that he explained to the concerned person that this has been done according to the Company's rules whereupon the concerned person shouted and said that the rules are made only for him and nobody





28-83 marked 1 to 12 Ext. 12 dt. 28-83 gives the programme of checking of trains. MW-3 Shri B. C. G. Singh has stated in his evidence that Ext. 12 is the letter from the FCI to him a copy of which was sent to the concerned person and he had also shown his copy of Ext. 12 to the concerned person and asked him to follow the checking programme as given in Ext. 12 but the concerned person did not follow the checking programme. He has further stated that the concerned person did not submit any report to him. It appears therefore that the concerned person disregarded the instruction given to him regarding the checking programme and the concerned person did not check according to the programme and submit his report as required vide Ext. 12.

The findings made above will show that some of the charges established against the concerned workman are not very serious but if the cumulative effect of all these charges are taken together it will appear that the concerned person was quarrelling with superior officers, hurling abuses against them and he also was deliberately disobeying the orders of his superiors in the performance of his duties. It is clear therefore that the various charges established against him show that he had committed misconduct of serious nature and was uncontrollable. Considering the above facts it appears that the punishment of dismissal passed against the concerned person was not severe.

In the result, I hold that the action of the management of M/s. Futwah Islampur Light Railway Co., Calcutta in dismissing the services of their workman Shri K. N. Prasad, Ex-Assistant Traffic Inspector w.e.f. 13-7-84 is justified and consequently the concerned person is entitled to no relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-41012/29/85-D.II(B)]

का. आ. 1936-—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के पठन के, केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि-करण, चण्डीगढ़ के पृचाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 जून, 1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1936.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th June, 1987.

BEFORE SHRI M. K. BANSAL PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. ID 83/85.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Food Corporation of India—Punjab Region.

AND

Their workman—Ajit Singh.

APPEARANCES:

For the Employers: Shri M. P. Vasudeva

For the workman: Shri O. P. Mehta

INDUSTRY : FCI

STATE : Punjab

AWARD

New Delhi, the 24th June, 1987

Vide Central Govt. Notification No. F-42012(48)/84-D.V dated 19-7-1985 issued under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, the following dispute was referred to this Tribunal for decision

Whether the action of the management of Food Corporation of India, in terminating the services of Shri Ajit Singh as Casual Watchman at their Jagroan Depot w.e.f. 12-5-83 and not giving an opportunity for his re-employment is justified and legal? If not, to what relief is the workman entitled for?"

2. The case of the workman is that he was working with the FCI at Jagroan on daily wages @ Rs. 13.00 per day. That he has worked for more than one year continuously without any break in service against permanent post. That services of the workman have been terminated on 12-5-1983 without payment of any retrenchment compensation. That in place of workman some other person as watchman have been recruited. So it was alleged that termination of his services is bad. He claimed reinstatement with back wage.

3. The management in their reply alleged that workman was appointed by the State Govt. as member of Punjab Home Guard so he is not workman. That the workman while guarding property of the FCI was rarely discharging the statutory duties under the Home Guard Act 1947. That services of the workman has been lent by State Govt. to the FCI. That FCI built its own godown and subject the goods lying in open to the said godowns and as such was not in need of the services of the workman and the workman was sent back. That there is no privity of Contract between the workman and the FCI and the FCI has no control over the work of the present workman. That workman was regularly recalled for training (weekly grades) and functions of his parent department. That workman was also recalled to assist the police as and when necessary. That workman remained with the FCI for 270 days from Jan. 1982 to December 1982.

4. In support of their respective allegation both the parties placed affidavit. Certain documents were also placed on the file.

5. Documents placed on the file by FCI include a letter alleged to have been received by FCI from one Rakinder Singh wherein it is stated that persons detailed in the list (which include workman also) are being sent to FCI for guarding their stock.

6. The counsel for the FCI placing reliance on the above contended that workman was member of the Home Guard and he was on deputation with the FCI, so he is not entitled to any compensation. I do not agree with this contention. It is not disputed that the workman worked with the FCI. FCI used to sanction leave to the workman. Control over the workman was of the FCI. So for all intents and purposes he is the employee of the FCI. He was paid salary by FCI.

7. On behalf of the workman 1986 (1) SLR 641 Food Corporation of India Vs. Presiding Officer, Industrial Tribunal cum-Labour Court (Central) Chandigarh and another an authority of Punjab and Haryana High Court has been cited. In the above authority workman who were member of the Home Guard, came to FCI to guard their stock. Their services were terminated. Question arose whether they have a right to get their services regularised or not. In the High Court the matter was decided on the basis of concessions made by counsel for FCI wherein he agreed that service will only be terminated by the management in accordance with law and for all intents and purposes they will be treated at par with regular employees (watchmen of the Corporation).

8. The second authority is of CWP No. 843/85 decided on 8-5-1985 by our own High Court in case No. FCI Vs. Presiding Officer, Industrial Tribunal-cum-Labour Court, (Central) Sector-17, Chandigarh. In the above case also workman were member of the Home guard and were on deputation with the Corporation. It was held by their Lordship that question whether services of workman could be terminated without payment of compensation is a debatable point and this point can only be decided in reference. As in the present case there was no reference so that point was not gone into. The above two case shows that workman were employees of the FCI.

9. The above two authorities shows that even if workman being a member of the Home Guard was working with the FCI being on loan his services could not be terminated without any compensation. It will also show that the workman become employee of the FCI. As his services were terminated without payment of any retrenchment compensation so termination is void.

10. Now, the next point to be determined is whether he worked for 240 days in one calendar year or not? It is admitted that employee worked with the FCI from January 1982 to Dec. 1982 for total number of 270 days i.e. more than 240 days. As services were terminated without payment of any retrenchment compensation so termination is void.

11. As a result of any above finding it is held that termination of the services of the workman vide order dated 17-5-1983 is void. Workman is entitled to reinstatement in service with continuity in service and back wages. Accordingly the reference is answered in favour of the workman.

Chandigarh:  
24-6-87

M. K. BANSAL, Presiding Officer.  
[No. L-42012/48/85-DV]

का.प्र. 1937.—प्रयोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम पंजाब रिजन के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निहित प्रयोगिक विवाद से केन्द्रीय सरकार 'प्रयोगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के संवत् को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 जून, 1987 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 1937.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award, of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab Region and their workmen which was received by the Central Government on the 30th June, 1987.

BEFORE SHRI M. K. BANSAL, PRESIDING OFFICER  
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM  
LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 66/1985

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of Food Corporation of India Regional Office Punjab.

#### AND

Their workman Piara Singh.

#### APPEARANCES:

For the employers—Shri M. P. Vasudeva

For the workman—Shri O. P. Mehta.

INDUSTRY: FCI

STATE: Punjab

#### AWARD

New Delhi, the 23rd June, 1987

Vide Central Govt. notification No. L-42012(41)/84-DV dated 26th March 1985 issued under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, the following dispute was referred to this Tribunal for decision.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Shri Piara Singh Watchman is just and legal? If not, to what relief the workman entitled to and from what date?"

2. The case of the workman is that he was working with the FCI at Jagroan on daily wages Rs. 12.40 per day. That he has worked for more than one year continuously without any break in service against permanent post. That services of the workman have been terminated on 8-7-1983 without payment of any retrenchment compensation. That in place of workman some other person as watch

been recruited. So it was alleged that termination of his services is bad. He claimed re-instatement with back wages.

3. The management in their reply alleged that workman was appointed by the State Govt. as member of Punjab Home Guard so he is not workman. That the workman while guarding property of the FCI was nearly discharging the statutory duties under the Home Guard Act 1947. That services of the workman has not been lend by State Govt. to the FCI. That FCI built its own godown and shifted the goods lying in the open to the said godowns and as such was not in need of the services of the workman and the workman was sent back. That there is no privity of contract between the workman and the FCI and the FCI has no control over the work of the present workman. That workman was regularly recalled for training (weekly parades) and functions of his parent department. That workman was also recalled to assist the police as and when necessary. That workman remained with the FCI from 7/82 to 7/83 for 233 days.

4. In support of their respective allegation both the parties placed affidavit. Certain documents were also placed on the file.

5. Documents placed on the file by FCI include a letter alleged to have been received by FCI from one Rakinder Singh wherein it is stated that persons detailed in the list (which include workman also) are being sent to FCI for guarding their stock.

6. The counsel for the FCI placing reliance on the above contents that workman was member of the Home Guard and he was on deputation with FCI, so he is not entitled to any compensation. I do not agree with this contention. It is not disputed that the workman worked with the FCI FCI used to sanction leave to the workman. control over the workman was of the FCI. So for all intents and purposes he is employee of the FCI.

7. On behalf of the workman 1986 (1) SLR 641 Food Corporation of India Vs. Presiding Officer, Industrial Tribunal-Cum-Labour Court. (Central) Chandigarh and another an authority of the Punjab and Haryana High Court has been cited. In the above authority workman who were member of the Home Guard, came to FCI to guard their stock. Their services were terminated. Question arose whether they have right to get their service regularised or not. In the High Court the matter was decided on the basis of concessions made by counsel for FCI wherein he agreed that services will only be terminated by the management in accordance with law and for all intents and purposes they will be treated at par with regular employees (watchman of the Corporation).

8. The second authority is of CWP No. 843/85 decided on 8-5-1985 by our own High Court in case Re-FCI Vs. Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Chandigarh Sector 17 Chandigarh. In the above case also workman were member of the Home Guard and were on deputation with the Corporation. It was held by their Lordships that question whether service of workman could be terminated without payment of compensation is a debatable point and this point can only be decided in reference. As in the present case there was no reference so that point was not gone into. The above two cases shows that workman were employee of the FCI.

9. The above two authorities shows that even if workman being a member of the Home Guard was working with the FCI being on loan his services could not be terminated without any compensation. It will also show that the workman become regular employees of the FCI. As their services were terminated without payment of any retrenchment compensation so termination is void.

10. Though in reply it was admitted by the FCI that workman worked during 7/82 to 12/82 for 130 days and during 1/83 to 7/83 for 103 days total 233 days, but in reply it was admitted that he worked from 4/82 to 12/82 for 150 days and from 1/83 to May 1983 for 88 days total 238 days i.e. more than 240 days during one calendar year. As such his services can not be terminated without compensation which admittedly have not been paid. So order

11. As a result of my above discussion it is held that services of workman can not be terminated without payment of retrenchment compensation so order of termination dated 8-7-83 is void. Workman is entitled to re-instatement in service with continuity in service and back wages. Accordingly the reference is answered in favour of the workman.

Chandigarh :

23-6-87

M. K. BANSAL, Presiding Officer.  
[No. L-42012/41/84-DV]

का.प्र. 1938.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम पंजाब रिजिन के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों द्वारा उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवादों में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पक्षाद को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30 जून, 1987 का प्राप्त हुआ था।

S.O. 1938.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh, is shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India Punjab Region and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th June, 1987.

BEFORE SHRI M. K. BANSAL, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I.D. 67/1985

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India, Punjab region.

#### AND

Their workman, Karnail Singh.

#### APPEARANCES :

For the Employers : Shri M. P. Vasudeva.

For the workman : Shri O. P. Mehta.

INDUSTRY : FCI,

STAFF : Punjab.

#### AWARD

Chandigarh, the 24th June, 1987

Vide Central Government notification No. L-42012(44)/84-D.V. dated 26th March, 1985 issued under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, the following dispute was referred to this Tribunal for decision :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in terminating the services of Shri Karnail Singh son of Shri Gurbux Singh Watchman is just and legal? If not to what relief the workman entitled to from what date?"

2. The case of the workman is that he was working with the FCI at Jagroan on daily wages @ Rs. 12-40 per day. That he has worked for more than one year continuously without any break in service against permanent post. That services of the workman have been terminated on 11-5-1983, without payment of any retrenchment compensation. That in place of workman some other person as watchman have been recruited. So it was alleged that termination of his services is bad. He claimed re-instatement with back wages.

3. The management in their reply alleged that workman was appointed by the State Government as member of Punjab Home guard so he is not workman. That the workman while guarding property of the FCI was merely discharging the statutory duties under the Home Guard Act, 1947. That services of the workman has been lend by State Government to the FCI. That FCI built its own godown and shifted the goods lying in open to the said godown and a watchman was not in need of the services of the workman and the workman was sent back. That there is no privity of Contract between the workman and the FCI and the FCI has no control

over the work of the present workman. That workman was regularly re-called for training (weekly parades) and functions of his parent Department. That workman was also re-called to assist the police as and when necessary. That workman remained with the FCI from April, 1982 to May, 1983 for 287 days.

4. In support of their respective allegation both the parties placed affidavit. Certain documents were also placed on the file.

5. Documents placed on the file by FCI include a letter alleged to have been received by the FCI from one Rakinder Singh wherein it is stated that persons detailed in the list (which include workman also) are being sent to FCI for guarding their stock.

6. The counsel for the FCI placing reliance on the above contended that workman was member of the Home Guard and he was on deputation with the FCI, so he is not entitled to any compensation. I do not agree with this contention. It is not disputed that the workman worked with the FCI. FCI used to sanction leave to the workman. Control over the workman was of the FCI. So far all intents and purposes he is the employee of the FCI.

7. On behalf of the workman 1936(1) SLR 641 Food Corporation of India Vs. Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh and another an authority of Punjab & Haryana High Court has been cited. In the above authority workman who were member of the Home Guard, came to FCI to guard their stock. Their services were terminated. Question arose whether they have a right to get their services regularised or not. In the High Court the matter was decided on the basis of concessions made by counsel for FCI wherein he agreed that services will only be terminated by the management in accordance with law and for all intents and purposes they will be treated at par with regular employees (watchmen of the Corporation).

8. The second authority is of CWP No. 843/85 decided on 8-5-1985 by our own High Court in case Re-FCI Vs. Presiding Officer, Central Govt., Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh, Sector-17, Chandigarh. In the above case also workman were member of the Home Guard and were on deputation with the Corporation. It was held by their Lordships that question whether services of workmen could be terminated without payment of compensation is a debatable point and this point can only be decided in reference. As in the present case there was no reference so that point was not gone into.

9. The above two authorities shows that even if workman being a member of the Home Guard was working with the FCI being on loan his services could not be terminated without any compensation. It will also show that the workmen become employees of the FCI. As their services were terminated without payment of any retrenchment compensation, so termination is void.

10. Now the next point to be determined is whether he worked for 240 days in one calendar year or not? It is admitted that employees worked with the FCI from April 1982 to May 1983 for total number of 287 days. The question to be determine is whether from April 1982 to March 1983 the worker worked for 240 days or not. This fact could have been proved by the FCI by producing their attendance register, by producing wage payment register to show that wages paid to the above worker for the actual working days was less than 240 days. In the absence of the above record being produced, a presumption will be drawn that the above person worked with the FCI for 240 days during the period from 1-4-1982 to 31-3-1983. It will also show that the workman become regular employee of the FCI. As their services were terminated without payment of any retrenchment compensation so termination is void.

11. As a result of my above finding it is held that termination of the services of the workman vide order dated 11-5-1983 is void. Workman is entitled to re-instatement in service with continuity in service and back wages. Accordingly the reference is answered in favour of the workman.

Chandigarh :

24-6-1987.

M. K. BANSAL, Presiding Officer.  
[No. L-42012/44/84-D.V.]

का आ 1989 - आवागमन द्वारा अधिनियम 1917 (1917 का 14) का धारा 17 के अन्तर्गत में फरीद लाल मालीय आयात निगम लुधियाना के एवमन में मध्यम निरीक्षण और उक्त कमरों के बाह्य अनुबंध में निहित आर्थिक निवार में केन्द्रिय सरकार अधिनियम अधिनियम के पत्रों का प्रमाणित करने के जो केन्द्रिय सरकार का 30 जून 1987 का प्राप्त हुआ था।

So 1939—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India Ludhiana and their workman which was received by the Central Government on the 30th June, 1987

BEFORE SHRI M. K. BANSAL PRESIDING OFFICER  
CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-  
LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. ID 7185

#### PARTIES

Employers in relation to the management of Food Corporation of India Punjab Region

AND

Their workman — Jagtar Singh

#### APPEARANCES

For the Employers— Shri M. P. Vasudeva

For the workman— Shri O. P. Mehta

INDUSTRY — FCI

STATE — Punjab

#### AWARD

Date 24-6-87

Vide Central Govt notification No. L 42012(39)/84 DV dated 13.5.1985 issued under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 the following dispute was referred to this Tribunal for decision

\* Whether the action of the management of Food Corporation of India, Ludhiana in terminating the services of Shri Jagtar Singh Watchman with effect from 17.1983 is justified? If not to what relief is the workman entitled?

2 The case of the workman is that he was working with the FCI at Jagraon on daily wages @ 17.40 per day. That he has worked for more than one year continuously without any break in service against permanent post. That service of the workman have been terminated on 17.1983 without payment of any retrenchment compensation. That in place of workman some other person as watchman have been recruited. So it was alleged that termination of his services is bad. He claimed with re-instatement with back wages.

3 The management in their reply alleged that workman was appointed by the State Govt as a member of Punjab Home Guard so he is not workman. That the workman while guarding property of the FCI was really discharging the statutory duties under the Home Guard Act 1947. That services of the workman has been lent by State Government to the FCI. That FCI built its own godown and shifted the goods lying in open to the said godowns and such is not in need of the services of the workman and the workman sent back. That there is no privity of Contract between the workman and the FCI and FCI has no control over the work of the present workman. That workman was

regularly recalled for training (weekly parades) and functions of his parent department. That workman was also recalled to assist the police as and when necessary. That workman remained with the FCI from March 1982 to February 1983 for 262 days.

4 In support of their respective allegation both the parties placed affidavit. Certain documents were also placed on the file.

5 Documents placed on the file by FCI include a letter alleged to have been received by FCI from one Rakinder Singh wherein it is stated that persons detailed in the list (which include workman also) are being sent to FCI for guarding their stock.

6 The counsel for the FCI placing reliance on the above contended that workman was member of the Home Guard and he was on deputation with the FCI, so he is not entitled to any compensation. I do not agree with this contention. It is not disputed that the workman worked with the FCI. FCI used to sanction leave to the workman. Control over the workman was of the FCI. His pay was given by FCI. So far all intents and purposes he is the employee of the FCI.

7 On behalf of the workman 1986(1) SLR 641 Food Corporation of India Vs Presiding Officer Industrial Tribunal cum Labour Court (Central) Chandigarh and another an authority of Punjab & Haryana High Court has been cited. In the above authority workman who were member of the Home Guard, came to FCI to guard their stock. Their services were terminated. Question arose whether they have a right to get their services regularise or not. In the High Court the matter was decided on the basis of concessions made by counsel for FCI wherein he agreed that services will only be terminated by the management in accordance with law and for all intents and purposes they will be treated at par with regular employees (watchmen) of the Corporation.

8 The second authority is of CWP 843/85 decided on 8th May, 1985 by our own High Court in case Re FCI Vs Presiding Officer, Industrial Tribunal cum Labour Court (Central) Sector 17, Chandigarh. In the above case also workmen were member of the Home Guard and were on deputation with the Corporation. It was held by Their Lordships that question whether services of workman could be terminated without payment of compensation is a debatable point and this point can only be decided in reference. As in the present case there was no reference so that point was not gone into.

9 The above two authorities shows that even if workman being a member of the Home Guard was working with the FCI (temp on loan) his services could not be terminated without any compensation. It will also show that the workman become employee of the FCI. As then services were terminated without payment of any retrenchment compensation so termination is void.

10 Now the next point to be determined is whether he worked for 240 days in one calendar year or not? It is admitted that employee worked with the FCI from March 1982 to February 1983 for total number of 262 days. This admission shows that the workman worked for more than 240 days in one year and become regular employee of the FCI. As his services were terminated without payment of any retrenchment compensation so termination is void.

11 As a result of my above finding it is held that termination of services of the workman vide order dated 17.1983 is void. Workman is entitled to re-instatement in service with continuity in service and back wages. Accordingly the reference is answered in favour of the workman.  
Chandigarh  
24-6-1987

M. K. BANSAL Presiding Officer  
[No. I-42012/39-84 D.V.]  
HARI SINGH Desk Officer